mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-29 अंक-318 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा
19 नवंबर 2025 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

विकेट को दोष देना...

@ पेज 7

सीजेआई बोले-न्याय की सक्रियता जरूरी लेकिन यह आतंक न बने

नई दिल्ली,एजेंसी। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को कहा कि देश में न्यायिक सक्रियता (ज्यूडिशियल एक्टिविज्म) जरूरी है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। यह सक्रियता कभी भी न्यायिक आतंकवाद (ज्यूडिशियल टेररिज्म) में नहीं बदलनी चाहिए। CJI गवई दिल्ली में पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एफ आई रिबेलो की किताब Our Rights: Essays on Law, Justice and the Constitution के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ समेत कई वरिष्ठ वकील और न्यायाधीश मौजूद थे। CJI गवई ने कहा कि जब भी विधायिका या कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल होती है, तब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालयों को आगे आना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जजों को किस सीमा तक न्यायिक सक्रियता अपनानी चाहिए, इसे जस्टिस रिबेलो ने अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है।

दिल्ली की 3 अदालतों 2 स्कूलों को बम की धमकी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की 3 जिला अदालतों और 2 स्कूलों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी अदालतों को खाली करवा लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धमकी भरा मेल जैश-ए-मोहम्मद नाम की मेल आईडी से भेजा गया था। इसके बाद तीनों कोर्ट कैंपस में बम स्क्वॉड जांच कर रहा है।

भारत की मेट्रो रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर, मंत्री खट्टर बोले- दो से तीन साल में अमेरिका भी होगा पीछे

हैदराबाद, एजेंसी। भारत तेजी से मेट्रो नेटवर्क विस्तार की ओर बढ़ रहा है और अब देश दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइनों वाले देशों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि भारत अगले दो से तीन साल में अमेरिका को मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई में पीछे छोड़ देगा। देश में शहरीकरण बढ़ने के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं लगातार तेज हुई हैं और इसी का परिणाम है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। हैदराबाद में साउथ-वेस्ट राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में मनोहर लाल ने बताया कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 1,100 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका 1,400 किलोमीटर पर है।

शाह ने तय की थी नक्सली हिड़मा की डेडलाइन

मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिड़मा एनकाउंटर में ढेर, पत्नी और 4 साथी भी मारे गए

जगदलपुर, एजेंसी। देश के सबसे खतरनाक नक्सल कमांडरों में शामिल माड़वी हिड़मा छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेडमिल्ली जंगल में मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी ढेर कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी ह्ढ्ढ ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले से इसकी पुष्टि की है।

एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षाबलों को हिड़मा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेडमिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी

ऑपरेशन में हिड़मा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया है। हिड़मा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले, 2021 सुकमा-बीजापुर हमले में भी हिड़मा की भूमिका रही है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र में भी एक दूसरी मुठभेड़ हुई है, इसमें नक्सलियों के घायल होने की खबर है। दोनों जगहों पर सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन टीम से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है।

हिड़मा दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड था

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में 76 जवानों की हत्या हुई थी। यह नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। उस हमले का मास्टरमाइंड हिड़मा ही था। इसमें बसवाराजू भी शामिल रहा, जो एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। बसवाराजू हमले के लिए बनी रणनीति की मीटिंग में शामिल हुआ था। हमले की साजिश रची थी।

आतंकी डॉ. उमर बोला-सुसाइड बॉम्बिंग शहीद होने का मिशन, दिल्ली धमाके से पहले बनाया वीडियो

आतंकियों की ड्रोन हमला करने की साजिश थी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में लाल किला के पास 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी डॉ. उमर का नया वीडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था। इसमें वह आत्मघाती हमले को लेकर बात रख रहा है। इससे माना जा रहा है कि वह फिदायीन हमला पहले से प्लान कर रहा था।

विडियो में उमर टूटी-फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने कहा- एक बात जो नहीं समझी गई कि यह शहीद होने के लिए ऑपरेशन (मार्टरडम ऑपरेशन) है, न कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास हैं। दरअसल मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है।

दरअसल, डॉ. उमर ने ही दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुंडई द्20 कार से आत्मघाती धमाका किया था। इस धमाके से 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें से 6 डॉक्टर है। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट नेटवर्क की पहचान में जुटी है।

आतंकी ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे

इधर, हमले की जांच में सोमवार रात बड़ा खुलासा हुआ है। NIA ने बताया कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। यह प्लानिंग हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। NIA को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर-उन-नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली। दानिश जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है। NIA ने उसे चार दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया।

ताइवान को लेकर चीन-जापान के बीच भारी तनाव

जापानी पीएम बोलीं- हमला हुआ तो सेना भेजेंगे; चीनी राजदूत बोले- दखल देने वालों की गर्दन काट देंगे

बीजिंग/टोक्यो, एजेंसी। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान पर दिए बयान से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल साने ताकाइची ने 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर-जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया। इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसल जनरल शुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे।इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आगाह किया है और चेतावनी दी है कि वहां जाने पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ते माहौल के बीच, रविवार को चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान के कंट्रोल वाले सेनकाकू आइलैंड के पास दिखाई दिए थे। इसके बाद जापान के कोस्ट गार्ड ने उन्हें इलाके से बाहर किया था।

जापानी पीएम साने ताकाइची

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

अमेरिका ने क्लियर किया कि जापान-अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है, तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा।वहीं, चीन के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ जापानी फिल्मों की रिलीज रोक दी है। चीनी सरकारी टीवी CCTV ने कहा कि यह घरेलू माहौल को देखते हुए यह फैसला सावधानी से लिया गया है।

वोटर लिस्ट रिवीजन- केरल के बाद तमिलनाडु में बायकॉट

केरल सरकार एसआईआर रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची; 12 राज्यों में 50.11 करोड़ फॉर्म बंटे

नई दिल्ली, एजेंसी। निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के BLO के साथ ही तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान किया है।

तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा कि वे वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और

मेहनताने विरोध में प्रदर्शन करेंगे।

इधर, केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक SIR स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनावों के साथ-साथ SIR कराना कठिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों-ञ् में अब तक 50.11 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 98.32% वोटर्स तक फॉर्म पहुंच गए हैं।

IUML ने SIR प्रक्रिया रोकने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि SIR और स्थानीय निकाय चुनावों को साथ-साथ नहीं कराया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि राज्य में 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनावों होने वाले हैं, जबकि SIR ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। इससे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

गुजरात के अरावली में एंबुलेंस में आग, 4 जिंदा जले

एक दिन के नवजात के इलाज के लिए जा रहा था पिता; डॉक्टर-नर्स की भी मौत

अहमदाबाद, एजेंसी। गुजरात के अरावली जिले में चलती एंबुलेंस में आग लग गई। इस हादसे में एक डॉक्टर, नर्स, एक नवजात शिशु और उसके पिता की मौत हो गई। हालांकि एंबुलेंस ड्राइवर और एक रिश्तेदार को बचा लिया गया। हादसा मोडासा की रणसैय्यद चोकड़ी के पास हुआ। एंबुलेंस अहमदाबाद के ऑरेंज अस्पताल की थी।

दरअसल, महिसागर जिले के

लुणावाड़ा निवासी जिग्नेशभाई महेशभाई मोची के नवजात (उम्र 1 दिन) बच्चे को इलाज के लिए मोडासा के रिच अस्पताल से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

सड़क पर जलती हुई एंबुलेंस का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो वहां मौजूद पेट्रोल पंप पर रिकॉर्ड हो गया था।

तीन लोग झुलसे, इलाज जारी एम्बुलेंस में आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी थी। हादसे में चालक अंकितभाई ठाकोर, (24), गौसंगकुमार मोची (40) और गीताबेन मोची (60) मामूली रूप से झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए अरावली के अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। मोडासा नगर पालिका के फायर ब्रिगेड के इंचार्ज हेमराज वाघेला ने कहा- रात का 1.40 बजे 101 नंबर पर कॉल आया था कि राणासैयद पास एक एंबुलेंस में आग लग गई है। फायर की टीम मौके पर पहुंची पर आग पर काबू पाया। मोडासा टाउन पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है।

सऊदी बस हादसा: नमाज-ए-जनाजा के लिए मृतकों के करीब 50 परिजन रवाना

खाड़ी देश पहुंची तेलंगाना सरकार की टीम

हैदराबाद,एजेंसी। सऊदी अरब में हुए भीषण बस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के लगभग 50 परिजन मंगलवार को नमाज-ए-जनाजा के लिए खाड़ी देश रवाना हुए। नमाज-ए-जनाजा गुरुवार को होने की संभावना है। तेलंगाना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

तेलंगाना सरकार की टीम सऊदी अरब पहुंची :तेलंगाना सरकार की टीम का नेतृत्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन कर रहे हैं। यह टीम राहत कार्य और नमाज-ए-जनाजा की तैयारियां करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है।

डीएनए मिलान के बाद दिए जाएंगे मृत्यु प्रमाणपत्र :अधिकारी

अधिकारी ने कहा, मृत्यु प्रमाण पत्र तभी दिए जाएंगे जब डीएनए मिलान होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सऊदी सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सकती है। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार और यात्रा बीमा से मिलने वाली राशि भी अलग होगी। डीएनए मिलान होना कानूनी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। तेलंगाना सरकार का राजस्व विभाग भी परिजनों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

हादसे में झुलसकर जिन लोगों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन्हें संरक्षित किया गया है। सऊदी जाने वाले परिजनों का डीएनए परीक्षण किया जाएगा, ताकि शवों की पहचान की जा सके और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।

पुतिन के भारत दौरे से पहले उनके करीबी पेत्रुशेव पहुंचे दिल्ली, एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय बातचीत का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सोमवार को नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात की। पेत्रुशेव रूस की समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वो सोमवार को भारत पहुंचे। बता दें, दिसंबर में पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है। रूसी दूतावास ने एक्स पर जानकारी दी कि पेत्रुशेव ने एनएसए डोभाल और भारत के राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता से बातचीत की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ अहम बातचीत कर रहे। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा एससीओ, ब्रिक्स और जी20 जैसे मंचों पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्रियों की यह चर्चा अगले महीने की शुरुआत में होने वाले 23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियों के लिए मंच तैयार करेगी। दोनों देश व्यापार संतुलन, भुगतान और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर भी काम कर रहे हैं। **विदेश मंत्री जयशंकर तीन दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे** :विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को तीन दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे।रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूसी विदेश मंत्रालय के द्वितीय एशिया विभाग के निदेशक एलेक्सी पावलोवस्की ने हवाई अड्डे पर जयशंकर का स्वागत किया विदेश मंत्री आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है, जिसमें एससीओ, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र तथा जी-20 के भीतर सहयोग का मुद्दा भी शामिल है।

राजस्थान के माउंट आबू में पारा शून्य,बद्रीनाथ में झील-झरने जमे

म.प्र. के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, स्कूलों की टाइमिंग बदली

नई दिल्ली, एजेंसी। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा माइनस 8 डिग्री चला गया है, जिससे वहां झरने और झीलें जम गई हैं।

राजस्थान में साल 2021 के बाद पहली बार नवंबर में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले

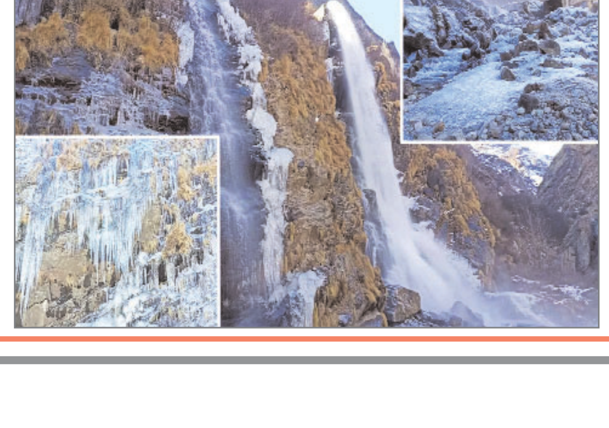

24 घंटे के दौरान फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य के 15 शहरों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। माउंट आबू में 15 साल में पहली बार नवंबर में ही पारा शून्य पर पहुंच गया है। इससे ओस की बूंदें जम गईं। पिछले साल माउंट आबू में पिछले साल ओस की बूंदें 10 दिसंबर 2024 को बर्फ बनी थीं।

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत 26 जिलों में मंगलवार को शीतलहर की चेतावनी दी गई है। इंदौर में आज से स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से कर दी गई है। भोपाल में नर्सरी से 8वीं क्लास तक स्कूलों की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे के बाद लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में सोमवार को 3 साल की सबसे ठंडी सुबह रही। सोमवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जे-स्लैब ट्रैक पर 320 की स्पीड से दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जानें क्या है इसकी खासियत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अत्याधुनिक जे-स्लैब ट्रैक सिस्टम पर दौड़ेगी। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित और स्थिर रेल टेक्नोलॉजी में से एक है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) पर जापान के सहयोग से देश में पहली बार इसे बिछाया जा रहा है। भूकंप प्रतिरोधी ट्रेक बुलेट ट्रेन की हाई-स्पीड को स्थिरता और सुरक्षा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिन पहले ही कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा कर सूरत में निर्माणाधीन स्टेशन का दौरा किया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी नई जानकारियों को पेश किया है। रेलवे के पवेलियन में मुख्य रूप से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर फोकस किया गया है।

यह ट्रेन 320 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार सेजे-स्लैब ट्रैक सिस्टम पर दौड़ेगी। यह सिस्टम वह तकनीक है जिसका उपयोग जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में किया जाता है। इसे विश्व की सबसे सुरक्षित रेल सेवा माना जाता है। इस ट्रैक का रखरखाव भी न के बराबर होता है।

समुद्र के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी टनल: इस कॉरिडोर पर महज 7 किलोमीटर का जमीन का ट्रेक है जबकि सबसे चुनौतीपूर्ण 21 किलोमीटर लंबा समुद्र के नीचे टनल बनाया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में 8 सुरंगें भी बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्रर की दृष्टि से 12 आधुनिक और सौंदर्यपूर्ण डिजाइन वाले स्टेशन, 3 रोलिंग स्टॉक डिपो, 8 रखरखाव केंद्र, साबरमती में हाई-स्पीड रेल मल्टी-मॉडल हब और वडोदरा में हाई-स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं।

जे-स्लैब ट्रैक में नहीं किया जाता गिट्टी का इस्तेमाल: सामान्य ट्रैक में गिट्टी का प्रयोग किया जाता जबकि जे-स्लैब ट्रैक में एक कठोर कंक्रीट संरचना तैयार की जाती है। इसमें चार मुख्य परतें होती हैं, जिनमें कंक्रीट ट्रैक बेड, सीमेंट डामर मोर्टार परत, पूर्व-निर्मित ट्रैक स्लैब और फास्टनरों वाली पटरियां शामिल हैं।

53 स्टील और रिवर ब्रिज से गुजरेगी ट्रेन: 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 53 बड़े पुलों के ऊपर से गुजरेगी।

इनमें 28 स्टील ब्रिज और 25 रिवर ब्रिज शामिल हैं। प्रोजेक्ट में 465 किलोमीटर (मार्ग का लगभग 85 प्रतिशत) पुलों पर बनना है। 326 किलोमीटर के मार्ग पर पुलों का काम पूरा हो चुका है। 17 नदी पुलों का निर्माण पहले ही हो चुका है।

इन शहरों को जोड़ेगी बुलेट ट्रेन: रेलवे पवेलियन में बताया गया कि यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 348 किमी. गुजरात, 4 किमी. दादरा एवं नगर हवेली और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में आते हैं।

दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण पर एमसीडी से नाराज, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा

नई दिल्ली, एजेंसी। बढ़ते वायु प्रदूषण और बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एमसीडी से नाराज हैं। दोनों महत्वपूर्ण मोर्चों की कमान दिल्ली सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। 11 नवंबर को समीक्षा बैठक के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एमसीडी इन मोर्चों पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ मिलकर खुद ग्राउंड स्तर पर सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी करने का फैसला किया है। सीएम ने हाल में आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में एमसीडी के कामकाज पर तीखी नाराजगी जताई थी। बैठक में यह तथ्य सामने आया था कि धूल-नियंत्रण मशीनें पूरी क्षमता से नहीं चल रहीं, कई वार्डों में कूड़ा उठाने में देरी हो रही है और सड़क धुलाई का सिस्टम लगभग ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि दिल्ली प्रदूषण के गंभीर दौर में है। ऐसे में किसी भी विभाग की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती लेकिन सिर्फ नाराजगी जताना ही पर्याप्त नहीं था। बैठक के चार दिन बाद भी जब कई इलाकों से सुधार की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिली, तो मुख्यमंत्री ने सीधे हस्तक्षेप का निर्णय लिया।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह संदेश साफ कर दिया गया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल एमसीडी की नहीं, बल्कि सीधे दिल्ली सरकार की निगरानी में होगी। सरकार ने तय किया है कि सोमवार को सभी छह मंत्री विभिन्न

क्षेत्रों में सफाई और प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की प्रत्यक्ष समीक्षा करने पहुंचे।

एमसीडी को चेतावनी: दिल्ली सरकार में बैठक के बाद एमसीडी आयुक्त ने भले ही जोनल उपायुक्तों के साथ आपात बैठक कर निर्देश जारी कर दिए हों लेकिन सरकार उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रही। एमसीडी को साफ संदेश दिया गया है कि अब कामकाज की जिम्मेदारी और उसकी निगरानी दोनों सरकार के हाथ में रहेगी। दिल्ली में जैसे-जैसे हवा खराब होती जा रही है, वैसे-वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता दिल्ली सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर ढीली पड़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सफाई और प्रदूषण नियंत्रण का मोर्चा खुद संभालना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

कर्ज.. तनाव और खौफनाक कदम : दिल्ली में युवक ने पेट्रोल डालकर लगाई आग, व्यापार में हो गया था लाखों का नुकसान

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 29 वर्षीय युवक ने बढ़ते कर्ज और उधार देने वालों के दबाव के चलते अपने किराए के कमरे में खुद को आग लगा ली, हालांकि वह बच गया। यह जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 9.50 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जल गया है और उसे बीएलके अस्पताल लाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि घायल की पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। उसकी हालत स्थिर है।

पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की मौजूदगी में सिंह का बयान दर्ज किया। अधिकारी ने बताया, विशाल ने कहा कि उसके व्यवसाय में तीन से चार लाख रुपये का नुकसान हुआ था और वह समय पर किराया नहीं दे पा रहा था। उसने दो लोगों से पैसा उधार लिया था और वे लगातार रुपये लौटाने का दबाव बना रहे थे। तनाव में आकर उसने कमरे में खुद को आग लगा ली। उसकी पत्नी और पड़ोसियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि आगे के उपचार के लिए सिंह को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस सीटें बढ़ने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली जगह

स्वमधुरिमास ने की शिक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील

दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभागों और कॉलेजों में पिछले तीन साल से सहायक प्रोफेसर के पदों पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया से कॉलेजों में शिक्षकों के 85 फीसदी सीटों को भरा जा चुका है लेकिन कॉलेजों और विभागों को शिक्षकों के लिए इंडब्लयूएस सीटें आवंटित नहीं की गई है जबकि ईडब्लयूएस बड़ी सीटों के आंकड़े मंगवाए जा चुके हैं।

फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस विवि शिक्षक संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर डीयू के लिए जल्द इंडब्लयूएस सीटों को आवंटित करने की मांग की है। फोरम का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू होने के चाद से चार वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। स्नातक स्तर के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके लिए कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है।

चार वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होने से कॉलेजों में शिक्षकों की मांग बढ़ी: फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया है कि डीयू के सहायक कुलसचिव कॉलेजिज ने ढाई साल पहले विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों के प्राचार्यों तथा संस्थान के निदेशकों से ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी अतिरिक्त पदों की आवश्यकता के विषय में जानकारी मांगी थी।

प्रो सुमन ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र चौथे वर्ष में प्रवेश कर अध्ययन कर रहे हैं जिससे हर कॉलेज के विभागों में शिक्षकों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है।

दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के लिए एक ही फास्टैग सिस्टम लागू होगा, एक टैग से होगा पूरा टोल भुगतान

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल वाहनों को अब दो अलग-अलग टैग फास्टैग और एमसीडी केआरएफआईडी टैग नहीं रखने पड़ेंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने टोल कलेक्शन सिस्टम को फास्टैग से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे ड्राइवरों को रिचार्ज और टैग मैनेजमेंट की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नई टेंडर प्रक्रिया के बाद लागू होगा सिस्टम अधिकारियों के अनुसार, नया फास्टैग आधारित सिस्टम एक नई कंपनी के चयन के बाद लागू किया जाएगा। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद किया जा रहा है, जिसमें सभी कॉमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) लागू करने की अनुमति दी गई है। पहले एमसीडी के आरएफआईडी सिस्टम को फास्टैग से जोड़ने में दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि ईसीसी के नियम अलग थे। खाली ट्रकों पर कम शुल्क लगता था, जबकि फल-सब्जी और जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों पर शुल्क नहीं लगता था। फास्टैग सिस्टम इन अलग-अलग नियमों को संभालने में सक्षम नहीं था।

अमेरिकी आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख डेविड रिचर्डसन का इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख डेविड रिचर्डसन ने महज छह माह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा टेक्सास बाढ़ प्रबंधन को लेकर आलोचनाओं के बीच आया है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की। बताया गया है कि एजेंसी प्रमुख रिचर्डसन ने सोमवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इसी साल आठ मई को संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने उनके पूर्ववर्ती कैमरन हैमिल्टन को अचानक हटा दिया था। इस एजेंसी का नेतृत्व करने से पहले रिचर्डसन होमलैंड सुरक्षा विभाग के सामूहिक विनाश के हथियारों के निरोधक कार्यालय में सहायक सचिव थे।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी की चीफ ऑफ स्टाफ करेन इवांस पहली दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगी। प्रवक्ता ने रिचर्डसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें निजी क्षेत्र में

उनकी वापसी करने की बधाई दी है। रिचर्डसन का इस्तीफा जुलाई में सेंट्रल टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद एजेंसी की प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच आया है। इस बाढ़ में 157 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

इस आपदा के समय संपर्क न हो पाने के लिए रिचर्डसन की तीखी आलोचना हुई। आलोचकों में कैपिटल हिल के सांसद भी शामिल थे। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाहक प्रमुख से घंटों संपर्क नहीं हो पाया, जिससे खोज और बचाव दल तैनात करने के प्रयास जटिल हो गए।

चीन के दबाव में तिब्बती शरणार्थी की नेपाली नागरिकता और पासपोर्ट की जांच शुरू

काठमांडू, एजेंसी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से जुड़े और 'फ्री तिब्बत अभियान' का गैर-आधिकारिक राजदूत माने जाने वाले गावंग छोक्डुप की नेपाली नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच नेपाल में चीनी दूतावास की तरफ से दबाव बनाने के बाद शुरू हुई है। सोलुखुम्बु जिला प्रशासन कार्यालय जांच कर रहा है कि तिब्बती मूल के छोक्डुप ने नेपाली नागरिकता और पासपोर्ट किस प्रकार प्राप्त किया। सोलुखुम्बु की प्रमुख जिला अधिकारी लीला कुमारी केसी पांडे ने उनकी नागरिकता पर जांच शुरू होने की पुष्टि की। उन्होंने यह भी बताया कि छोक्डुप को बयान के लिए बुलाया जा चुका है। इस विषय पर गृह मंत्रालय के सूचना अधिकारी उप-सचिव रविन्द्र आचार्य ने कहा कि जिस जिले से नागरिकता जारी हुई है, वही जिला इसकी जांच करेगा। इसलिए यह कार्य वर्तमान में सोलुखुम्बु जिला प्रशासन कर रहा है।

नेपाल के गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल से 14 अक्टूबर को नेपाल में चीनी राजदूत छेन सोंग ने मुलाकात के दौरान जेन-जी आंदोलन में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में फ्री तिब्बत मूवमेंट के युवाओं की राजनीतिक सक्रियता पर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर तेन्जिंग दावा को जिला अदालत काठमांडू में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया था। वैसे तो उसे सोशल मीडिया के एक पोस्ट के कारण नियंत्रण में लिया गया था, जिसमें उसने पिस्टल के साथ रील बनाई थी। इस समय दावा काठमांडू जिला पुलिस के रिमांड पर है। इसके तुरंत बाद ही काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की तरफ से विदेश मंत्रालय के मार्फत गृह मंत्रालय को कूटनीतिक नोट लिखते हुए नेपाल में तिब्बती शरणार्थी को नेपाली नागरिकता दिए जाने और उनकी राजनीतिक सक्रियता पर चिंता जताई गई थी। विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी ने बताया कि चीनी दूतावास की तरफ से भेजे गए इस डिप्लोमेटिक नोट में दलाई लामा के नेपाल प्रतिनिधि के नेपाली नागरिकता और पासपोर्ट की जांच करने का आग्रह किया गया था।

छोक्डुप को 'फ्री तिब्बत अभियान' का गैर-आधिकारिक राजदूत माना जाता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने 19 अगस्त, 2022 को उन्हें काठमांडू स्थित तिब्बती शरणार्थी सामुदायिक कार्यालय के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। काठमांडू के लाजिम्पाट क्षेत्र में स्थित यह कार्यालय नेपाल में मौजूद विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा कूटनीतिक मिशनों से समन्वय करता है और तिब्बती शरणार्थियों की सहायता से जुड़े कार्य संभालता है। दलाई लामा से भेंट कर शपथ लेने के बाद छोक्डुप 3 नवम्बर, 2022 को नेपाल आए और पदभार ग्रहण किया। दिलचस्प तथ्य यह है कि नेपाल आने से पहले ही उन्होंने सोलुखुम्बु से नेपाली नागरिकता ले ली थी। तीन साल के कार्यकाल के लिए आए छोक्डुप की नागरिकता संख्या 111003-44 है, जिसमें उनका उपनाम शेरपा दर्ज है। इसी नागरिकता के आधार पर उन्होंने 2014 में पासपोर्ट बनवाया। 07703381 नंबर का वह पासपोर्ट 2 अगस्त, 2024 को समाप्त होना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही एक और पासपोर्ट निकाल लिया है। 1 अप्रैल 2019 को जारी उनके दूसरे पासपोर्ट का नंबर 11381810 है, जिसकी वैधता 31 मार्च, 2029 तक है। इस पासपोर्ट के माध्यम से वे दर्जनों बार विदेश यात्रा कर चुके हैं।

काठमांडू स्थित चीनी राजदूत के लगातार दबाव के बाद छोक्डुप की नागरिकता और पासपोर्ट पर जांच शुरू की गई, जिसके बाद वह 22 अक्टूबर को सड़क मार्ग से नई दिल्ली होते हुए हिमाचल प्रदेश स्थित दलाई लामा के मुख्यालय धर्मशाला चले गए। 11 मई, 1982 को जन्मे छोक्डुप शुरू में सोलुखुम्बु स्थित 'देलेक्लिंग चिल्सा तिब्बती शरणार्थी शिविर' में रहते थे। यह शिविर नेपाल में मौजूद 12 तिब्बती शरणार्थी शिविरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका की गाजा शांति योजना को मंजूरी दी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को अमेरिकी प्रस्ताव पारित कर दिया। इसका उद्देश्य गाजा में नाजुक युद्धविराम से आगे बढ़कर अधिक स्थायी शांति और तबाह हुए क्षेत्र के पुनर्निर्माण की ओर बढ़ना है। 15 सदस्यीय परिषद ने प्रस्ताव के पक्ष में 13-0 से मतदान किया। रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दोनों ने इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। सीएनएन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान करना था। इस योजना के कुछ हिस्से पिछले महीने गाजा पट्टी में लागू युद्धविराम का आधार बने। अमेरिका ने इसे पारित कराने के लिए कड़ी पैरवी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ ही क्षण पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अविश्वसनीय मतदान पर विश्व को बधाई। शांति बोर्ड की अध्यक्षता मैं करूंगा और विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेता इसमें शामिल होंगे।

पारित प्रस्ताव के अनुसार, अब शांति बोर्ड की स्थापना और गाजा में अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) का गठन किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों की घोषणा

जल्द की जाएगी। कई राजनयिक सूत्रों ने कहा कि इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल है। इसलिए अन्य राष्ट्रों को आईएसएफ में शामिल होने में कोई बाधा नहीं आएगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइकल वाल्ट्ज ने कहा कि आईएसएफ शांति सैनिकों का मजबूत गठबंधन होगा। इसमें इंडोनेशिया, अजरबैजान और अन्य मुस्लिम बहुल देशों के सैनिक शामिल होंगे। गाजा में एक एकीकृत कमान के तहत इनकी तैनाती होगी। गाजा की सड़कों को सुरक्षित किया जाएगा। शांति सैनिक विसैन्यीकरण की निगरानी करते हुए नागरिकों की रक्षा करेंगे। सुरक्षित गलियारों के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मतदान से पहले वाल्ट्ज ने चेतावनी दी थी कि इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान का मतलब युद्ध की ओर लौटना होगा।

पश्चिमी राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि प्रस्ताव में विस्तृत जानकारी का अभाव इसे लागू करने में मुश्किल पैदा करेगा। संक्रमणकालीन प्राधिकारी फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपे जाने की स्पष्ट समय-सीमा न होने के कारण इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पारित प्रस्ताव में शांति बोर्ड को 2027 के अंत तक के लिए किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि शांति बोर्ड हमास और अन्य गुटों के निशस्त्रीकरण और गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करेगा। सनद रहे यह मांग इजराइल लंबे समय से करता रहा है।

इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी राज्य का भी उल्लेख है, लेकिन इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। मसौदे में कहा गया है, सुधार कार्यक्रम के ईमानदारी से लागू होने और गाजा पुनर्विकास के आगे बढ़ने के बाद फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्य के दर्जे के लिए एक विश्वसनीय मार्ग के लिए परिस्थितियां अंततः तैयार हो सकती हैं। इसमें कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद स्थापित करेगा ताकि शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक राजनीतिक क्षितिज पर सहमति बन सके। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बोर्ड के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया गया है।

हमास ने रविवार को कहा कि वह इस मसौदा प्रस्ताव को गाजा पर अंतरराष्ट्रीय संरक्षण थोपने और कब्जे के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का एक प्रयास मानता है। सोमवार को हुए मतदान के बाद हमास ने कहा कि किसी भी स्थिरीकरण बल को गाजा पट्टी के अंदर तैनात करने से संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। हमास कई अधिकारियों ने कहा कि उसकी सैन्य शाखा को निशस्त्र करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमास लड़ाके गाजा में प्रतिशोध की मांग कर रहे अन्य समूहों से खुद को बचाने के लिए हल्के हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दोहराया, गाजा का विसैन्यीकरण हर हाल में किया जाएगा।

पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 विद्रोही मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 15 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षाबलों के साथ 15 और 16 नवंबर को हुई मुठभेड़ों में 15 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं।

आईएसपीआर के मुताबिक विद्रोहियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर, सुरक्षा बलों ने डेरा इस्माइल खान जिले के कुलाची इलाके में एक अभियान चलाया। अभियान के दौरान विद्रोहियों के सरगना आलम महसूद सहित दस अन्य विद्रोही लड़ाके मारे गए ।

एक अन्य अभियान में उत्तरी वज़ीरिस्तान जिले के दत्ता खेल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाँच और विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है।

प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में पहल- आयोग के सचिव ने कलेक्ट्रेट में की विस्तृत समीक्षा बैठक

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की दिशा में आयोजित प्रथम चरण की बैठक आयोग के सचिव अक्षय सिंह, आईएएस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की दक्षता बढ़ाने, जन-सुविधा को सुदृढ़ करने, तथा भौगोलिक वास्तविकताओं के आधार पर युक्तियुक्त पुनर्गठन की आवश्यकता पर विस्तृत विमर्श करना था।

बैठक के दौरान प्रशासनिक इकाइयों की कार्यप्रणाली, वर्तमान चुनौतियों, विभागीय समन्वय की स्थिति तथा कार्यक्षेत्र के बोझ जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। सचिव अक्षय सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य जन अपेक्षाओं के अनुरूप संभाग, जिला, उपखंड, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर की प्रशासनिक इकाइयों का ऐसा पुनर्गठन करना है, जिससे प्रशासन अधिक सुगम, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बन सके।

बैठक के उपरांत सिंह ने तहसील एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों का अवलोकन किया तथा कर्मचारियों से सीधे संवाद कर दैनिक कार्यप्रवाह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि वास्तविक परिस्थितियों और मैदानी स्तर की आवश्यकताओं को आयोग के प्रस्ताव तैयार करते समय प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी राजेश शुक्ला, उपखंड अधिकारी कुसमी विकास आनंद, सिहावल प्रिया पाठक, गोपद बनास राकेश शुक्ला, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दलित-आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार रोकने की मांग, भाकपा ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

भेदभाव की घटनाओं पर जताई चिंता

मीडिया ऑडिटर, सिंगरौली (निप्र)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। यह पहल पार्टी के 'देशव्यापी सामाजिक न्याय और समानता अभियान' के तहत की गई।

अत्याचार और भेदभाव की घटनाओं पर जताई चिंता: पार्टी नेताओं ने बताया कि देशभर में कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं पर हिंसा और दमन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों से देश के संवैधानिक मूल्य और सामाजिक सद्भाव दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

दलित-आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन का आरोप: ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। जमीन, वन और अन्य संसाधनों पर उनके परंपरागत अधिकार सुरक्षित न होने से वे आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर कड़ी आपत्ति: इस दौरान नेताओं ने महिलाओं पर बढ़ते बलात्कार, हिंसा और शोषण की घटनाओं को गंभीर बताते हुए कहा कि यह देश की संस्कृति और संविधान की समानता एवं गरिमा की भावना के विपरीत है। भाकपा ने केंद्र सरकार से कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बराबरी, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राष्ट्रपति से भी आग्रह किया गया कि वे हस्तक्षेप कर सरकारों को कड़े निर्देश जारी करें।

आंदोलन की चेतावनी: ज्ञापन सौंपने पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर शासन द्वारा समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भाकपा जन आंदोलन को और तेज करेगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही, अनुपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर होगी कार्रवाई; कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। धौहनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गईं। इस लापरवाही पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, मझौली को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि, भारत निर्वाचन आयोग 28 अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस काम के लिए बीएलओ के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

निरीक्षण में कई केंद्रों पर मिली अनुपस्थिति: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि 17 नवंबर को क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी पर मौजूद नहीं थीं। इनमें दरिया, दियाडोल, सिलवार, डांगा, ताला और खडौरा केंद्रों की कार्यकर्ता शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ बीएलओ द्वारा भी अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

लापरवाही को माना गया दंडनीय अपराध: अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थिति और असहयोग गंभीर लापरवाही है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है।

अवैतनिक करने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया है कि अनुपस्थित और असहयोगी कार्यकर्ताओं को अवैतनिक किया जाए। साथ ही सभी को चेतावनी दी गई है कि वे 18 नवंबर 2025 से बीएलओ को एसआईआर कार्य में पूरा सहयोग दें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नशामुक्त भारत अभियान की पाँचवीं वर्षगांठ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में नशामुक्त भारत अभियान की पाँचवीं वर्षगांठ के अवसर पर 18 नवंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु जागरूक किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. देवेंद्र कुमार सोनी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें स्वयं भी नशे से दूर रहना है और दूसरों को भी नशे से बचने के लिए जागरूक करना है, तभी हमारा देश वास्तव में नशामुक्त बन सकेगा।

ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, खेत की जुताई के दौरान हादसा; संभलने का मौका नहीं मिला

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। मड़वास थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर खेत में जुताई के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से 30 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना अमहा गांव में हुई। मृतक की पहचान अमहिया सोंधिया निवासी गब्बूचन्द उर्फ बाबूलाल साहू के रूप में हुई है। दुर्घटना दोपहर लगभग 12 बजे घटी, जब किसान अपने खेत में जुताई कर रहा था। बताया गया कि जुताई के दौरान ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर पलट गया। गब्बूचंद ट्रैक्टर के नीचे दब गए और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही नदहा, अमहा, सोंधिया और अमहिया सहित आसपास के कई गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मड़वास थाना प्रभारी भूपेश बैस भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

एक्सीडेंट का मामला: थाना प्रभारी भूपेश बैस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला एक दुर्घटना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा, 'हमें सूचना मिलते ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया यह एक्सीडेंट का मामला लग रहा है। ट्रैक्टर पलटने के कारण युवक की दबकर मौत हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है।

कचरे का संकट, 24 वार्डों में सफाई ठप; 33 आउटसोर्स कर्मी वेतन न मिलने से हड़ताल पर

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। शहर की सफाई व्यवस्था मंगलवार सुबह से पूरी तरह ठप हो गई है। नगर पालिका के आउटसोर्स सफाईकर्मियों ने वेतन और अन्य भुगतानों में देरी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल से शहर के सभी 24 वार्डों में सफाई कार्य प्रभावित होगा।

सफाईकर्मियों के अनुसार, पिछले चार साल से उनका पीएफ जमा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें नौ महीने से एरियर और डेढ़ महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इन वित्तीय समस्याओं के कारण कुल 33 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। हड़ताल पर बैठे सफाईकर्मी सिद्धार्थ भारती ने बताया कि वेतन भुगतान में लगातार देरी होती रही है, कभी दो तो कभी तीन महीने बाद वेतन मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इंचार्ज कहते हैं कि 'जब मन पड़ेगा तब वेतन देंगे, काम करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो।' भारती ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल में सिद्धार्थ भारती, सुनील भारती, सागर भारती, नंदू भारती, नीरज और सुदर्शन सहित कुल 33 सफाईकर्मी शामिल हैं। इस संबंध में सफाईकर्मी इंचार्ज गौरव सिंह ने बताया कि उनका कार्य केवल कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कर सीएमओ को भेजना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन जारी करने का अधिकार उनके पास नहीं है और सीएमओ की ओर से अभी तक वेतन संबंधी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं, जब सीएमओ मिनी अग्रवाल से इस मामले पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

एप पर पैसे का दिया लालच, बैंक से निकाले रुपए; पीड़िता ने एसपी से की शिकायत

मीडिया ऑडिटर, सिंगरौली (निप्र)। साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। विन्धनगर थाना क्षेत्र के गहिलगढ़ निवासी उर्मिला देवी डीटी ऐप के जरिए 6 हजार रुपए की ठगी का शिकार हो गईं। पीड़िता को एक ऐप डाउनलोड कराया गया था, जिसमें वीडियो देखने पर पैसे मिलने का लालच दिया गया था। उर्मिला देवी ने इस झांसे में आकर ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उनके बैंक खाते से दो बार में कुल 6 हजार रुपए काट लिए गए।

महिला ने जनसुनवाई में की शिकायत: ठगी का शिकार होने के बाद उर्मिला देवी ने एक सप्ताह तक बैंक और स्थानीय थाने के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल के अधिकारी पवन सिंह को तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी की अपील- अनजान लिंक पर क्लिक न करें एसपी मनीष खत्री ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध मैसेज या ऐप डाउनलोड करने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मामले की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल में दें, ताकि ठगी से बचा जा सके।

7000 से अधिक बच्चे कुपोषित, 1600 अति गंभीर; लेकिन पुनर्वास केंद्र में इस महीने सिर्फ 5 बच्चे हुए भर्ती

मीडिया ऑडिटर, सिंगरौली (निप्र)। कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले में 7000 से अधिक बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, जिनमें लगभग 1600 बच्चे अति गंभीर कुपोषित (सअम) श्रेणी में हैं। इसके बावजूद, जिला मुख्यालय बैढ़न स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में कुपोषित बच्चों की भर्ती दर बेहद धीमी है। आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 7000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इनमें से लगभग 1600 बच्चे अति गंभीर कुपोषित (सअम) हैं, जबकि 5300 से अधिक बच्चे सामान्य कुपोषण (सअम) से जूझ रहे हैं। यह स्थिति महिला और बाल विकास विभाग के जमीनी अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

इस महीने अभी तक सिर्फ 5 बच्चों को भर्ती कराया गया: अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में पूरे जिले से पोषण पुनर्वास केंद्र में मात्र 187 बच्चों को भर्ती कराया गया। यह संख्या जिले में कुपोषण की भयावह स्थिति के मुकाबले काफी कम है। नवंबर माह में केवल 5 कुपोषित बच्चों को भर्ती किया गया, जबकि अगस्त में 40, सितंबर में 22 और अक्टूबर में 9 बच्चों को भर्ती किया गया था। भर्ती संख्या में यह लगातार गिरावट विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

अधिकारी बोले- कर्मचारी लगातार काम कर रहे: महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि कर्मचारी लगातार काम कर रहे है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि बच्चे एनआरसी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो यह एक गंभीर विषय है। गुप्ता ने कहा कि वे इसकी समीक्षा कर सही स्थिति स्पष्ट करेंगे।

80 वर्षीय वृद्धा को खाट पर अस्पताल ले गए परिजन, से लोग बोले- क्षेत्र में सड़क-स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी समस्या

मीडिया ऑडिटर, सिंगरौली (निप्र)। देवसर क्षेत्र से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़क सुविधा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। ग्राम चुरवाही की 80 वर्षीय बिथुनी शाहू को खाट पर अस्पताल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना करीब एक सप्ताह पुरानी है। वृद्धा अचानक गंभीर बीमार हुईं तो परिवार ने डायल-100 पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। लेकिन वह लगभग दो घंटे देर से पहुंची। हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उन्हें खाट पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना शुरू किया।

घर से सड़क तक एक किलोमीटर पगडंडी, वाहन पहुंचना मुश्किल: वृद्धा के बेटे प्रदीप शाह ने बताया कि उनके घर से मुख्य सड़क तक करीब एक किलोमीटर लंबा संकरा पगडंडी मार्ग है। इस रास्ते पर वाहन नहीं पहुंच पाते, इसलिए मजबूरी में खाट का सहारा लेना पड़ा। मुख्य मार्ग पर आने के बाद परिजनों ने निजी वाहन से बिथुनी शाहू को जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। उपचार मिलने के बाद उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी समस्या प्रदीप शाह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा और सड़क निर्माण की स्थिति अब भी बेहद कमजोर है। कई गांवों में अब तक सड़क नहीं पहुंची है, जिसके कारण गंभीर मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को खाट या चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है। लंबी पगडंडी और एम्बुलेंस की देरी अक्सर बड़ी परेशानी बन जाती है।

जिला पंचायत सीईओ बोले- जल्द करेंगे समाधान: इस मामले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गेमें ने कहा कि उन्हें गांव में सड़क न होने की जानकारी मिली है। जनपद सीईओ से चर्चा कर इस समस्या का समाधान जल्द निकालने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुधारकर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं।

जाहिर सूचना

क्र0-18/25 दिनांक-18/11/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु प्रताप सिंह पिता श्री हरभजन सिंह, निवासी ग्राम खुजवा सुखदेव सिंह, जिला रीवा (म.प्र.) Flat No. A-12, area 707 sqft. Built up area 667 sqft. Third Floor of the multy Storey Building Named "S.B. Complex" Built on partial area of 12200 sqft. Of Aaraji Khasra No. 44/1 Village/Mauja Bara, J.No. 394, Municipal Corporation Rewa Ward no. 11, Patwari Halka Rewa-31, Circle Rewa Gird, Vikashkhand Rewa, Tehsil Huzur, Distt. Rewa (M.P.) के मालिक/आधिपत्यधारी है। उक्त फ्लैट नीलामी में विक्रेता Piramal Capital & Housing Finance Ltd. (In Short PCHFL) Formerly known as Dewan Housing Finance Corporation Limited- (DHFL), Having Its Registered Office at Warden House 2nd, Floor Sir PM Road Fort Mumbai, Maharastra 400001, & Having its Branch Office, Plot No. 11, Alankar Complex Mezzanine Floor, Bank Street, MP Nagar Zone-II Bhopal MP Authorized Officer, Mr. Gaurav Shrvastav S/o K.B. Shrivastav R/o Narmada Road, Distt. Jabalpur (M.P.) से क्रेता विष्णु प्रताप सिंह पिता श्री हरभजन सिंह, निवासी ग्राम खुजवा सुखदेव सिंह, जिला रीवा (म.प्र.) ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP328492024A11291102 पंजीकरण दिनांक 29/10/2024 उपपंजीयक कार्यालय रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) से क्रय की थी, उक्त फ्लैट की मूल रजिस्ट्री क्रमांक 5436 दिनांक 27/10/2006 वर्तमान भूमिस्वामी विष्णु प्रताप सिंह पिता श्री हरभजन सिंह को नीलामीकर्ता/विक्रेता Piramal Capital & Housing Finance Ltd. द्वारा प्रदान नही की गई है। जिसके संबंध में वर्तमान भूमिस्वामी विष्णु प्रताप सिंह द्वारा स्व-हस्ताक्षरित नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान फ्लैट मालिक श्री विष्णु प्रताप सिंह पिता श्री हरभजन सिंह, निवासी ग्राम खुजवा सुखदेव सिंह, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा उक्त भूमि को बंधक कर शुभम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा रीवा (म.प्र.) से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। जिसमें मूल रजिस्ट्री क्रमांक 5436 दिनांक 27/10/2006 की आवश्यकता है, जो फ्लैट मालिक को नही मिली है एवं उसके फ्लैट मालिक द्वारा कहीं बंधक गिरवी आदि नही किया गया है। उक्त विक्रय पत्र एवं ऋण के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो वह इस प्रकाशन के सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय अथवा शुभम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाखा रीवा (म.प्र.) में प्रस्तुत करे। प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी तथा भावी ऋण प्रदान कर दिया जावेगा।

भवदीय
राजेन्द्र त्रिपाठी एडवोकेट,
रीवा (म0प्र0)

सांसद ने ग्रामीणों की 24 शिकायतें सुनीं, 5 किमी पैदल चले; अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। लोकसभा सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने मंगलवार सुबह सरदा पंचायत के ग्राम पनिहा का निरीक्षण किया। वे ग्रामीणों से मिलने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और कुल 24 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों में सड़क सुधार, पेयजल व्यवस्था, बिजली की अनियमित आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गंभीर मुद्दे शामिल थे। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण राजवीर सिंह ने बिजली विभाग से जुड़ी अपनी समस्या बताई। उन्होंने जानकारी दी कि बिजली कनेक्शन कटने के बावजूद उन्हें लगातार बिल प्राप्त हो रहे हैं। सांसद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल जांच और समाधान के निर्देश दिए। अन्य ग्रामीणों ने भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कई शिकायतें प्रस्तुत कीं।

सांसद मिश्रा ने ग्रामीणों की प्रत्येक समस्या को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि जनता की वास्तविक जरूरतों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचना सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ पैदल चलकर कई स्थानों का आकलन किया और जिन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, उन पर तुरंत निर्देश दिए। जिन कार्यों में अधिक समय लगने की संभावना थी, उनके लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा गया।

ग्रामीणों के साथ बैठकर किया चाय-नाश्ता: दौरे के दौरान सांसद मिश्रा ने ग्रामीणों के साथ बैठकर सुबह का नाश्ता किया। ग्रामीणों ने इस कदम को सकारात्मक और विश्वास बढ़ाने वाला बताया। उनका कहना था कि जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनने से समाधान की उम्मीदें मजबूत होती हैं। सांसद ने आश्वासन दिया कि पनिहा और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरे में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के साथ सीधी जनपद पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार और जनपद पंचायत सीईओ चंदूलाल पनिका भी उपस्थित थे।

शेख हसीना को सजा, बांग्लादेश का भविष्य और अधिक संकट में

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जिस तरह भारत से मांग की कि वह शेख हसीना को उन्हें सौंपे, उससे भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह तय है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला। इसलिए और भी, क्योंकि ट्रिब्यूनल को कंगारू कोर्ट बता रहीं शेख हसीना उसके फैसले को चुनौती दे सकती हैं।

बांग्लादेश का भविष्य संकट में- बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की ओर से भारत में शरण लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाने से ऐसी प्रतीति होना स्वाभाविक है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने यह फैसला सुनाया है, लेकिन यह तो अंतरराष्ट्रीय नाम वाला बांग्लादेश का अपना न्यायाधिकरण है, जिसके जज से लेकर वकील तक मोहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की ओर से तय किए गए।

इस ट्रिब्यूनल की वैधानिकता और विश्वसनीयता उतनी ही संदिग्ध है, जितनी अंतरिम सरकार की। शेख हसीना को सजा सुनाने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि उसने छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के समय पुलिस प्रमुख रहे चौधरी अब्दुल्ला को केवल पांच वर्ष की सजा सुनाई।

संपादकीय

इससे इन्कार नहीं कि शेख हसीना सरकार के समय जो आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़का, उसमें अनेक लोग मारे गए थे, लेकिन तथ्य यह भी है कि यह आंदोलन भी हिंसक था और उसका उद्देश्य तख्ता पलट था। इस आंदोलन के निशाने पर अवामी लीग के समर्थकों के साथ पुलिस कर्मी भी थे।

इसकी भी अनदेखी न की जाए कि इस आंदोलन के दौरान जिन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे, उनमें से कई अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। निःसंदेह सत्ता में रहते समय शेख हसीना ने पुलिस को हिंसक छात्र आंदोलन से निपटने के आदेश दिए होंगे, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना विचित्र है कि उनके कहने पर छात्रों की हत्या की गई। तथाकथित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से शेख हसीना के खिलाफ ऐसे ही किसी कठोर फैसले की भरी-पूरी आशंका थी, क्योंकि वहां की अंतरिम सरकार को वे फूटी आंख नहीं सुहा रही थीं।इसका पता इससे चलता है कि उनकी पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर उसे चुनाव में भाग लेने से पहले ही रोका जा चुका है। इसके अलावा हिंसक आंदोलन की भेंट चढ़े लोगों की मौतों का संज्ञान नहीं लिया गया। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद यह और स्पष्ट है कि बांग्लादेश में होने जा रहे चुनावों के समय उनके समर्थकों का दमन होगा। इन चुनावों में कट्टरपंथी संगठनों को जिस तरह भाग लेने की अनुमित दे दी गई है, उससे बांग्लादेश का भविष्य और अधिक संकट में दिख रहा है।

पाकिस्तान में सेना प्रमुख की बढ़ी ताकत, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

मृत्युंजय दीक्षित

दरकता पाकिस्तान कई नागरिक समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को जुटाने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनवा जैसे प्रान्त सुलग रहे हैं। हुक्मरान इनको दबाने के लिए सीमाओं पर आग लगा रहे हैं। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भी पाकिस्तान की ओर लग रहा है। इन सबके बीच जिस तरह पाकिस्तान की सेना प्रमुख की शक्तियों को संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है वह भविष्य के लिए खतरनाक संकेत दे रहा, क्योंकि सेना प्रमुख मुनीर लगातार आतंकवाद को संरक्षण व पूरा सहयोग कर रहा है।

पाकिस्तान में सेना प्रमुख को मिली शक्तियों के अनुसार अब जब कभी पाकिस्तान का भारत या अफगानिस्तान के साथ युद्ध होगा तब सेना प्रमुख मुनीर ही परमाणु हमला करने का फैसला करेगा। मुनीर को परमाणु हमला करने की यह शक्ति उस समय मिली है जब कुछ दिनो पूर्व ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि पाकिस्तान चोरी छिपे तथा रूस, चीन और कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण कर कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे।

पाकिस्तान की संसद ने सेना प्रमुख आसिफ मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार मुनीर को चीफ आफ डिफेंस फोर्सज बनाया जा रहा है। यह 27 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। पद मिलते ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमांड मिल जाएगी। अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बने रहेंगे और उन्हें आजीवन कानूनी छूट मिलती रहेगी अर्थात नए कानून के अनुसार अब आसिफ मुनीर को आजीवन कोई नहीं हटा सकेगा ।अब पाकिस्तान की संसद ने अदालतों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है जिसके अंतर्गत अब सरकार तय करेगी कि कौन से जज कौन सा केस सुनेंगे। अब जजों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे । पहले यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास था । अब अगर वहां की अदालत में कोई केस एक साल तक नहीं चला तो वह केस बंद कर दिया जाएगा। नए संविधान संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ताकत घट जाएगी और राष्ट्रपति नाम मात्र का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा।

पाकिस्तान के संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश की सेना और ताकतवर हो जाएगी। पाकिस्तान में अब तानाशाही का एक नया दौर देखने को मिल सकता है जो दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के विरोधी दल जहां इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं । वहीं प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ इसे राष्ट्रीय एकता के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। पाकिस्तान में आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव देश को सैन्य शासन की ओर ले जा रहा है।

पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां के आर्मी चीफ रिटायर हो जाने के बाद विदेश चले जाते थे लेकिन अब मुनीर न तो रिटायर होंगे और न ही विदेश जाएंगे। लेकिन क्या वहां के अन्य आर्मी कमांडरो को यह बात मंजूर होगी पाकिस्तान के इतिहास में यह परंपरा रही है कमांडर रिटायरमेंट के बाद यूरोप, सऊदी अरब या अमीरात में आराम का जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं । जनरल अशफाक परवेज कियानी से लेकर जावेद बाजवा तक ने अपने ठिकाने विदेश में बनाए और पूर्वसेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का हाल तो पता ही है क्या हुआ। किन्तु अब आसिफ मुनीर संविधान संशोधन की आड़ लेकर अपने पद पर अजर अमर हो रहे हैं। भारत भी आपरेशन सिंदूर के समय तय कर चुका है कि अब अगर भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो वह एक्ट आफ वॉर ही माना जाएगा। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हो चुका है जिसकी गहन जांच चल रही है और धमाके के लिंक जैश- ए -मोहम्मद से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं। मुनीर भारत से पंगा लेने के लिए बेचैन लग रहा है। पाकिस्तान को लगातार भय सता रहा है कि अबकी बार भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भी कम से कम चार फ्रंट पर युद्ध करना ही पड़ेगा और तब पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत पर परमाणु हमला करने की हिमाकत कर सकता है।

नीतीश कुमार की अगुवाई में सा गठन के संकेत और बदलते केंद्र-राज्य समीकरणों का परिदृश्य

बिहार ने 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों के साथ भारतीय राजनीति को एक बार फिर चौंकाया है। जिस प्रकार के जनादेश ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है, वह न केवल राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने वाला क्षण है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस जनादेश के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में शपथ-ग्रहण संपन्न हो सकता है, और बिहार एक बार फिर स्थिर शासन की ओर कदम बढ़ाएगा।

कांतिलाल मांडोत

यह चुनाव केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं, राजनीतिक मूल्यों और विकास के नए मानकों की अभिव्यक्ति भी है। बिहार लंबे समय से राजनीतिक उठापटक और गठबंधन परिवर्तनों का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार का फैसला अपेक्षा से कहीं अधिक स्पष्ट और निर्णायक है। इससे देशभर में यह संदेश गया है कि जनता बार-बार अस्थिरता, अनिर्णय और नकारात्मक राजनीति को नकार रही है।

नीतीश कुमार की वापसी अनुभव, विश्वसनीयता और प्रशासन का भरोसा है।

नीतीश कुमार पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्रीय चेहरा रहे हैं। भले ही वे कई बार राजनीतिक गठजोड़ों में बदलाव करते रहे हों, लेकिन एक बात सदैव कायम रही है और वो उनकी प्रशासनिक विश्वसनीयता है।सड़क-परिवहन और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन,महिलाओं के लिए आरक्षण तथा शराबबंदी जैसे सामाजिक सुधार आदि इन कदमों ने उन्हें आज भी बिहार की राजनीति में एक स्वीकार्य नेता बनाए रखा है।

2025 के चुनाव में बिहार ने उनके अनुभव पर दोबारा भरोसा जताया है। जनता यह संदेश देना चाहती थी कि राज्य को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो राजनीतिक अस्थिरता से ऊपर उठकर शासन को केंद्र में रखे। यही कारण है कि उनकी नेतृत्व क्षमता के इर्द-गिर्द गठबंधन की जीत को एक मजबूत जनादेश के रूप में देखा जा रहा है।

*शपथ-ग्रहण को लेकर बढ़ती उत्सुकता और बिहार में स्थिरता के संकेत मिल रहे है।चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही राज्य में नए मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा तेज है।

राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि19 या 20 नवंबर के बीच नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ-ग्रहण संभव है।तेजी से आगे बढ़ती यह प्रक्रिया दर्शाती है कि गठबंधन में स्पष्ट एकता और नेतृत्व को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इसकी दो महत्वपूर्ण वजहें हैं।

जनादेश बेहद स्पष्ट है और विपक्ष बिखरा हुआ दिखा। गठबंधन नेतृत्व पर विश्वास और भाजपा, जदयू और अन्य सहयोगी दलों में इस बार तालमेल पहले से अधिक मजबूत दिख रहा है।

शपथ-ग्रहण का यह चरण सिर्फ सरकार के औपचारिक गठन भर का विषय नहीं, बल्कि जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि नई सरकार समय गंवाए बिना अपने वादों और योजनाओं पर काम शुरू करेगी।

चुनावी परिणाम से राष्ट्रीय राजनीति को दिया यह संदेश जनता के विश्वास का प्रतीक है।

बिहार का चुनाव अक्सर देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला माना जाता है। 1970 के दशक की छात्र राजनीति से लेकर मंडल-कमीशन, सामाजिक न्याय और हाल के वर्षों में विकास और सुशासन बिहार की राजनीति हमेशा व्यापक राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करती आई है।

2025 के चुनाव परिणामों ने एक बड़ा संकेत दिया है।यह केवल नीतीश कुमार या ह्रष्ठ की जीत नहीं, बल्कि विपक्षी दलों की रणनीति, नेतृत्व संरचना और मतदाताओं से संवाद की विफलता का भी परिणाम है।

इस चुनाव ने स्पष्ट किया कि नकारात्मक राजनीति,भ्रम फैलाने की कोशिशें,जातिगत ध्रुवीकरण या अनर्गल आरोपों से मतदाता अब प्रभावित नहीं होता। यह प्रवृत्ति 2024 के लोकसभा चुनावों में भी दिखी थी, लेकिन बिहार के जनादेश ने इसे और मजबूत किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार का यह चुनाव आने वाले वर्षों में राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है कि मतदाता अब सिर्फ विकास, रोजगार, सुरक्षा और स्थिर प्रशासन चाहता है।

केंद्र-राज्य संबंधों में नए समीकरण सहयोग की नई परिभाषा बयां करते है।

इस जीत के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत यह उभर रहा है कि बिहार में केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते नए और सकारात्मक मोड़ पर जा सकते हैं।

सहयोगवादी संघवाद को गति एवं केंद्र में NDA और बिहार में उसी गठबंधन की सरकार होने का सीधा मतलब है कि अधिक विकास परियोजनाएँ तेजी से स्वीकृत होंगी।आर्थिक सहायता और अनुदान के आवंटन में रुकावटें कम होंगी। केंद्र की योजनाएँ राज्य में सरलता से लागू होंगी। बिहार जैसे राज्य को, जिसका विकास सूचकांक ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है, यह तालमेल नई ऊर्जा देगा। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास को नया बल मिलेगा। केंद्र सरकार पहले से ही पूर्वी समृद्धि कॉरिडोर, गंगा जलमार्ग ,पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, औद्योगिक हब तथा कृषि-आधारित उद्योग जैसी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। अब नए राज्य नेतृत्व के साथ समन्वय बढ़ेगा औरबिहार में निवेश-परिदृश्य बेहतर हो सकता है। सुरक्षा और सीमा-प्रबंधन को मजबूत समर्थनमिलेगा।

बिहार की नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा मुद्दों और सीमांचल बेल्ट की संवेदनशीलता को लेकर केंद्र अक्सर विशेष फोकस रखता है।

नए राजनीतिक समीकरण यहाँ बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई में मदद कर सकते हैं।

राजनीतिक स्थिरता से प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधारहोगा और इतना ही नही, राजनीतिक स्थिरता से अफसरशाही को स्पष्ट दिशा मिलेगी।परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और केंद्र-राज्य संयुक्त समितियों में निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे।

यह सभी कारक मिलकर आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए बड़ा अवसर पैदा करते हैं।बिहार में बदलती राजनीतिक दिशा से जनता की प्राथमिकताएँ बदल रही है। यह चुनाव यह भी दर्शाता है कि बिहार में राजनीति की मूल दिशा बदल रही है।

जाति-आधारित राजनीति की पकड़ कमजोर विकास केंद्र में है।हालाँकि बिहार की सामाजिक संरचना जातियों पर आधारित है, लेकिन इस चुनाव में जनता ने विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचे और शासन-व्यवस्था को प्राथमिकता दी।युवाओं की निर्णायक भूमिका

बिहार के युवा अब ऐसे नेतृत्व को पसंद करते हैं जो रोजगार, तकनीकी शिक्षा, स्टार्ट-अप और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर काम करे। महिला मतदाताओं का प्रभाव नीतीश कुमार की सरकारों ने महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण और जनहित योजनाओं से जोड़ा है।इसका लाभ लगातार मिलता रहा है।2025 में भी महिला मतदाता निर्णायक रहीं।

कानून-व्यवस्था प्राथमिक मुद्दा है।बिहार की जनता अब किसी भी कीमत पर अराजकता या अस्थिरता नहीं चाहती।

यह मानसिकता 2025 के जनादेश में साफ दिखाई दी।

विपक्ष की चुनौतियाँ पुनर्गठन की आवश्यकता है।विपक्ष इस चुनाव में नेतृत्व, संगठन और रणनीति के स्तर पर काफी कमजोर साबित हुआ।

अब विपक्ष के सामने कई चुनौतियाँ हैं।नेतृत्व का अभाव,

स्थानीय मुद्दों से दूरी, भाजपा-जदयू गठबंधन के मजबूत संगठन से मुकाबला,

युवा और महिला मतदाताओं को स्पष्ट एजेंडा न दे पाना।

अगर विपक्ष को भविष्य में मजबूत चुनौती पेश करनी है, तो उन्हें नए चेहरों, नई सोच और जमीनी रणनीति पर काम करना होगा। आने वाले 5 वर्षों का रोडमैप बिहार की महत्वाकांक्षाएँ

नई सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य होंगे। रोजगार सृजन और औद्योगीकरण

कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा. बुनियादी ढांचे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को विश्वसनीय बनाना और

सीमांचल और पिछड़े जिलों पर विशेष फोकस रहेगा।

टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्रशासन- भ्रष्टाचार-रहित शासन सुनिश्चित करना और इन लक्ष्यों पर वास्तविक प्रगति ही आने वाले वर्षों में सरकार की सफलता तय करेगी। 2025 का बिहार चुनाव परिणाम एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोड़ है। यह न केवल राज्य की नई दिशा तय करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी संदेश देता है किजनता अब स्थिरता, विकास और सुशासन का समर्थन करती है।नकारात्मकता, भ्रम और अनिश्चित गठबंधनों का दौर समाप्त हो रहा है।

नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली नई सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। केंद्र-राज्य संबंधों में सहयोग की नई परिभाषा उभर रही है, जो बिहार के विकास के लिए एक निर्णायक कारक साबित हो सकती है।अभी शपथ-ग्रहण की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, और बिहार एक नई राजनीतिक सुबह की ओर अग्रसर है। एक ऐसी सुबह, जिसमें स्थिरता, विकास और राष्ट्रीय समन्वय की नई कहानी लिखी जा सकती है।बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है।

उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के साथ ही विद्रोह का ग्रहण!

उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किया है । पार्टी ने उत्तराखंड में बड़ा बदलाव करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बार फिर अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है इसके अलावा पार्टी ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की है।

डॉ श्रीगोपाल नारसन

गणेश गोदियाल ने करण महारा का स्थान लिया है।करण महारा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। गोदियाल दो बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वह सन 2012 के विधानसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे।उत्तराखंड के लिए पार्टी ने नया प्रभारी भी नियुक्त किया है। मनोज यादव अब उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बनाये गए है। इसके साथ ही प्रदेश में 27 नए जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। अल्मोड़ा से भूपेंद्र सिंह भोज, बागेश्वर से अर्जुन चंद्र भट्ट, देहरादून सिटी से डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, हरिद्वार से बलेश्वर सिंह, रुद्रप्रयाग से कुलदीप कंडारी और टिहरी से मुरारी लाल खंडवाल को अध्यक्ष बनाया गया।सन 2017 और सन 2022 के विधानसभा चुनाव और सन 2024 के लोकसभा चुनाव में गोदियाल हार गए थे। जुलाई 2021 में भी वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन सन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और महारा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।उत्तराखंड कांग्रेस में जिला और महानगर

कमेटी के गठन के बाद कही कही बगावत भी हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे समेत 12 पार्षदों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इन पार्षदों ने सर्च कमेटी के निर्णयों पर सवाल उठाए है और कांग्रेस द्वारा की गई रायशुमारी को नाटकबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा।उन्होंने सर्च कमेटी के निर्णयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मनोनयन ही करना था तो रायशुमारी क्यों की गईउधम सिंह नगर कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से हिमांशु गाबा को बनाया गया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा को हटाकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ममता रानी को रुद्रपुर शहर की कमान सौंपी गई है। जिसके बाद कांग्रेस के 12 पार्षदों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही है।कांग्रेस पार्षदों ने सिटी क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि पहले ही कांग्रेस की चुनाव में काफी हालत खराब हैं,अब फिर से अध्यक्ष रिपीट करना कार्यकर्ताओ का अपमान है।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस संगठन सृजन में हम बहुत अच्छी संख्या में, जिलों में ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नौजवानों को जिम्मेदारी पर दे सकेंगे। हरीश रावत के इस बयान से नए सियासी समीकरणों को लेकर भी बहस छिड़ गई है। पहली बार कांग्रेस खुलकर ब्राह्मण वर्ग को ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात कर रही है। ऐसे में इसे कांग्रेस की नई सोच का परिणाम माना जा रहा है। क्या 2027 में कांग्रेस ब्राह्मण वर्ग को अधिक तवज्जो देने जा रही है, या कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पर ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा ब्राह्मण वर्ग से सीएम रह चुके हैं। जबकि ठाकुर के रूप में हरीश रावत को मौका मिला था। उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर की सियासत में संतुलन बिठाया जाता रहा है। जब ब्राह्मण सीएम हो तो ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और जब ठाकुर सीएम हो तो ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है।ब्राह्मण वर्ग में गणेश गोदियाल और किशोर उपाध्याय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि किशोर अब भाजपा में हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने एक बयान में कहते हैं सनातन, कांग्रेस और ब्राह्मण इन तीनों का मेल है। इनके मेल का जब भी संयोग बना है इसने देश को मजबूत किया है। संगठन में बदलाव से पहले ही उन्होंने इशारों में बता दिया था कि कांग्रेस ब्राह्मण वर्ग का खासा ख्याल रखने वाली है।सन 2017 से सन 2022 के बीच ठाकुर मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है।सन 2017 में जहां भाजपा को लगभग 53प्रतिशत ठाकुर वोट मिला था, सन 2022 में यह बढ़कर 60 प्रतिशत पर पहुंच गया। दूसरी ओर कांग्रेस का हिस्सा 29प्रतिशत से घटकर 26प्रतिशत रह गया।ब्राह्मण वोट बैंक में तो बदलाव और भी तेज रहा। सन 2017 में भाजपा को इस समुदाय से 52प्रतिशत वोट मिला था, जो सन 2022 में बढ़कर 63प्रतिशत तक पहुंच गया, यानी सीधे 11प्रतिशत की छलांग लगाई। इसके मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर 28प्रतिशत से गिरकर 26प्रतिशत रह गया।इसके उलट दलित समुदाय में कांग्रेस का ग्राफ ऊपर गया है। भाजपा का दलित वोट शेयर सन 2017 के 37प्रतिशत से गिरकर सन 2022 में 26प्रतिशत रह गया, जबकि कांग्रेस का समर्थन बढ़ा है।उत्तराखंड में ठाकुर (35प्रतिशत) और ब्राह्मण (25प्रतिशत) मिलाकर कुल 60प्रतिशत सवर्ण वोट शेयर बनाते हैं, जबकि बाकी सभी वर्ग-अल्पसंख्यक (16प्रतिशत), एसटी-ओबीसी (18.9प्रतिशत) और एससी (2.81प्रतिशत) सिर्फ 40प्रतिशत हैं।तभी तो अभी तक हर मुख्यमंत्री भी इन्हीं दो वर्गों से बने हैं।(लेखक राजनीतिक चिंतक वरिष्ठ साहित्यकार है)

कार्यालयों के चक्कर लगा रहे फुटपाथ व्यसायी

नोटिस के बाद अफरातफरी, सही जानकारी नहीं मिलने से नाराजगी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले ठेला संचालकों को नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सही जानकारी नहीं मिलने से वे नगर पालिका से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पिछले चार दिनों से इन व्यापारियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, जिससे उनके परिवार के भरण-पोषण की चिंता बढ़ गई है। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका ने 14 नवंबर को ये नोटिस जारी किए थे। इसमें सड़क किनारे ठेले लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को तत्काल अपना सामान हटाने का निर्देश दिया गया है। नगर पालिका का तर्क है कि सड़क किनारे दुकानों से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। नोटिस में सामान नहीं हटाने पर जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

कलेक्टर ने दुकानदारों की शिकायत नहीं सुनी: नोटिस मिलने के बाद जब फुटकर व्यापारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई जिले के कलेक्टर के आदेश पर की जा रही है। इसके बाद व्यापारी कलेक्टर एमसीबी से मिलने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया। मौखिक रूप से उन्हें बताया गया कि फुटपाथ पर दुकान लगवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है और उन्हें वापस नगर पालिका कार्यालय जाना चाहिए।

फुटपाथ व्यापारी परेशान, प्रशासन से वैकल्पिक जगह की मांग: फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब्ती की कार्रवाई से वे काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सकें। व्यापारियों ने बताया कि नोटिस देने आए कर्मचारी ने उन्हें भूपेंद्र क्लब में ठेला लगाने को कहा था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नगर पालिका ने उन्हें वहां से भी हटा दिया।

इस स्थिति में व्यापारी असमंजस में हैं कि वे अब कहां जाएं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है और इन छोटे व्यापारियों को कोई स्थायी समाधान मिल पाता है या नहीं।

खूबत बाबा मंदिर निर्माण विवाद गहराया, रजक समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के सतनबाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एनएच 46 पर खूबत घाटी में रजक समाज के प्रसिद्ध सिद्ध स्थल खूबत बाबा प्राचीन मंदिर के निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में, आज (मंगलवार) रजक समाज के सदस्यों ने एकजुट होकर शिवपुरी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को एक ज्ञापन सौंपा है।

निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप: रजक समाज का कहना है कि मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए टीनशेड और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। समाज ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि पुजारी पक्ष के कोमल शिवहरे, हेमा शिवहरे और नारायणी शिवहरे इन निर्माण कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के सदस्यों का आरोप है कि समझाने पर ये लोग गाली-गलौज और झगड़ा करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, मंदिर के ताले भी समय पर नहीं खोले जाते, जिससे पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

पंचायत का फैसला न मानने पर रोष: रजक समाज के जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने बताया कि यह मंदिर उनके पूर्वजों द्वारा पूजा के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समय के साथ इसमें मनमानी बढ़ती गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन संबंधित पक्ष ने पंचायत के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया।

एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025-26 अंतर्गत मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से Enumeration Form वितरण किया जाना है एवं वितरण पश्चात वापस प्राप्त फॉर्म का सत्यापन करना एवं सत्यापन के पश्चात् अपलोडिंग, डिजिटाइजेशन का कार्य 04 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में आपको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 02 मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत अनुभाग संख्या 63 के लिए बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। संदर्भित पत्र के माध्यम से आयुक्त सह अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका निगम चिरमिरी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपको 930 गणना पत्रक वितरण/वापसी हेतु दिया गया था, किन्तु आपके द्वारा 243 गणना पत्रक का ही वितरण किया गया है. तथा 17 नवंबर 2025, समय दोपहर 01:00 बजे तक की स्थिति में Enumeration form Digitization शून्य (0) होने व शेष गणना पत्रक वितरण नहीं किये जाने के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विपरीत असर हुआ है। फोन लगाने पर भी आपके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 (अनुबंध 1.2) के अधीन दंडनीय है।

शिवपुरी में किसान आक्रोश, कम तौल और पुलिस अभद्रता पर 3 घंटे भीषण चक्काजाम

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के भौंती थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव में किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा। फसल कम तौलने और थाने में पुलिस की अभद्रता से नाराज किसानों और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनपुरा मुख्य मार्ग पर लगभग तीन घंटे तक चक्काजाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और दर्जनों वाहन फंसे रहे।

क्यों हुआ प्रदर्शन कम तौल और थाने में अभद्रता: यह पूरा विवाद 9 नवंबर को शुरू हुआ था। मनपुरा के गल्ला व्यापारी वीरेंद्र बिलैया किसान रामदास लोधी की मूंगफली खरीदने गए थे। तय वजन 41 किलो 300 ग्राम प्रति बोरी था। किसान रामदास लोधी को कम तौल का शक हुआ। जब गांव से दूसरा कांटा मंगवाकर वजन किया गया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ: प्रत्येक बोरी में 2 किलो का अंतर था। इस पर विवाद बढ़ गया। मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने कांटा और व्यापारी का वाहन रोक लिया। मामला भौंती थाने पहुंचा, जहां पीड़ित किसान रामदास लोधी ने एक गंभीर आरोप लगाया: थाने में आरक्षक आनंद जैन ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। इसके अलावा, भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच भी तीखी नोकझोंक और झूमाझटकी हुई, जिससे दो दिनों तक थाने में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

मुख्य मार्ग पर 3 घंटे जाम- तनाव का माहौल: कम तौल और पुलिसकर्मी की अभद्रता के विरोध में सोमवार दोपहर 2 बजे ग्रामीणों, पीड़ित किसान रामदास लोधी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने मनपुरा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों की स्पष्ट मांग थी कि जब तक पुलिसकर्मी और संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक जाम खत्म नहीं होगा। लगभग तीन घंटे तक चले इस प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई।

उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप- आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम: शाम करीब 5 बजे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी प्रशांत शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के नेता अनिल गुर्जर, रामप्रीत गुर्जर, और मेहंद बौद्ध समेत अन्य आंदोलनकारियों से लंबी बातचीत की। एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही चक्काजाम समाप्त हुआ।

भरतपुर परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका भर्ती का प्रावधिक मूल्यांकन पत्रक जारी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एकीकृत बाल विकास परियोजना भरतपुर द्वारा विज्ञापन क्रमांक 217/स्था./मबावि/2025-26, 11 सितम्बर 2025 के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 05 पद तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 35 पद, कुल 40 पदों पर भर्ती हेतु पात्रताधारी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया कि - आंगनबाड़ी केन्द्र कुदरा हेतु सहायिका पद पर केवल 1 आवेदन, आंगनबाड़ी केन्द्र मनौरा, बनासटोला एवं स्कूलपारा रूसनी हेतु सहायिका पद पर केवल 2-2 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उक्त केंद्रों में आवेदनों की संख्या न्यूनतम मापदंड से कम होने के कारण इन 04 आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायिका पदों हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस बीच प्राप्त समस्त वैध आवेदनों का मूल्यांकन परियोजना स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। समिति द्वारा तैयार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 05 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 31 पद, कुल 36 पदों हेतु अनंतिम (प्रावधिक) मूल्यांकन पत्रक-परिशिष्ट-04 दिनांक 17 नवम्बर 2025 को निम्न स्थानों पर चस्पा किया जा रहा है- परियोजना कार्यालय, एकीकृत बाल विकास परियोजना भरतपुर, जनपद पंचायत भरतपुर का सूचना पटल, संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों के सूचना पटल

सभी आवेदिकाओं से अनुरोध है कि प्रकाशित सूची का अवलोकन कर लें। यदि सूची में दर्शित विवरण, संलग्न दस्तावेजों या अंकन के संबंध में किसी आवेदिका को आपत्ति हो, तो वे अपना दावा-आपत्ति 17 नवम्बर से 28 नवम्बर, सांय 05:30 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर परियोजना कार्यालय, भरतपुर में प्रस्तुत कर सकती हैं। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी दावादृआपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु चिरमिरी में विशेष वाहन चेकिंग अभियान

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (निप्र)। सरगुजा रेंज में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चिरमिरी थाना क्षेत्र में दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा तथा पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर रत्ना सिंह के निर्देशन में 17 और 18 नवंबर को संचालित हुआ।

नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में छोटी बाजार एवं गौदरीपारा मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक नाबालिग वाहन चालक पकड़ा गया, जिसके परिजनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181, 5/181 एवं 199-ए के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने नाबालिग के परिजन पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

इसी प्रकार शराब के नशे में वाहन चलाते हुए एक अन्य चालक पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी ने दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे बच्चों को मौके पर हेलमेट पहनाया और भविष्य में सदैव हेलमेट उपयोग करने की समझाइश दी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है।

जनदर्शन में 18 आवेदन हुए प्राप्त, आवेदनों को समय-सीमा पर करें निराकरण : कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुनी। जिले के ग्रामीणजन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक मानमती निवासी चौनपुर अंकसूची मे पुत्री व माता का नाम सुधार कराये जाने के संबंध मे, हेमा निवासी बुंदेली हैंड पम्प खनन करवाने के संबंध मे एवं शौचालय निर्माण कार्य की स्वीकृत करने के संबंध मे, एक्सीलेंट बुक स्टेसनरी मनेन्द्रगढ़ स्थानीय निर्वाचन मे मुद्रण कार्य के भुगतान के संबंध में, सोनाउ प्रसाद निवासी खोँगापानी मृत्यु प्रमाण पत्र देने के संबंध में, मंजूरी मुखर्जी निवासी चिरमिरी दूषित पानी एवं अपर्याप्त पानी सप्लाई सुधरने के संबंध में, अक्षय निवासी चिरमिरी पोंडी कुआ क्षतिग्रस्त एवं हनुमान मंदिर की मरम्मत करवाने के संबंध में, वेंकटेश अग्रवाल व हर्षित जैन निवासी मनेन्द्रगढ़ परसगढ़ी तपचं क्षेत्र के संबंध में, सरपंच फूलमती पाराडोल सड़क निर्माण के संबंध में, कृष्ण कुमार निवासी खोँगापानी पुत्री को वापस दिलाने एवं उचित न्याय करने के संबंध में, सुमित्रा निवासी चिरमिरी शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच में पायी गयी खाद्यान्न में कमी की भरपाई नहीं किये जाने पर कार्रवाही के संबंध में, विश्वनाथ सिंह निवासी मनेन्द्रगढ़ सीमांकन के संबंध में, प्रताप सिंह राज चिरमिरी 17 नवम्बर 2025 के संबंध में कारण बताओं का स्पष्टीकरण के संबंध में, विजेंद्र कुमार निवासी सेमरा किसान सम्मान निधि पुनः चालू करने के संबंध में, रामकृपाल निवासी बरबसपुर सड़क पर ओवरलोड वहन का संचालन के संबंध में, एवं शासकीय भूमि खसरा न. 199/1 रकबा 22.7060 हे. का मौका पर भौतिक सत्यापन कराये जाने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी घघरा भूमि सीमांकन के संबंध में, रामप्रताप सिंह निवासी पौराधार नामांतरण आदेश के उपरांत भी भूमि का नामांतरण नहीं हो पाने के संबंध में लेकर उपस्थित हुए थे।

मनेंद्रगढ़ ब्लॉक के पांच धान उपार्जन केंद्रों में हुई जोरदार शुरुआत, किसानों में उमंग

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का सीधा लाभ अब गांव-गांव के किसानों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से धान खरीदी की घोषणा किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। इसी क्रम में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में धान उपार्जन के दूसरे दिन पांचों केंद्रों में खरीदी की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। सभी केंद्रों में पूजा-अर्चना के बाद जैसे ही तौल मशीनें चलीं, किसानों के चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता झलक उठी। शासन की पारदर्शी प्रक्रिया, कड़ी निगरानी और बेहतर प्रबंधन के कारण सभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी सुचारू रूप से संपन्न हुई।

भरतपुर जनपद में नशा-मुक्त जनजागरूकता रैली का भव्य आयोजन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जनपद पंचायत भरतपुर द्वारा मंगलवार को नगर पंचायत जनकपुर में व्यापक जनजागरूकता रैली एवं जागरूकता समारोह का भव्य आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जनकपुर बस स्टैंड क्षेत्र से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूह की सदस्याओं, पंचायत कर्मियों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराती आगे बढ़ी।

रैली के दौरान प्रतिभागियों ने शराब, तंबाकू, गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों से होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक नुकसान की जानकारी आमजन तक पहुँचाई। जगह-जगह पोस्टर, बैनर और प्रेरक नारों के माध्यम से लोगों को नशा मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश दिया गया। नागरिकों को नशा मुक्त भारत की प्रेरणादायक शपथ भी दिलाई गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हीरालाल मौर्य ने कहा कि नशा समाज और परिवार की जड़ों को कमजोर करता है, इसलिए ऐसी जनजागरूकता गतिविधियाँ समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। वहीं जनपद सीईओ अजय सिंह राठौर ने रैली में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार जताया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही नशामुक्त समाज निर्माण संभव है।

कार्यक्रम में जनपद सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी, महिला समूहों की कार्यकर्ता, युवाओं एवं ग्रामीणजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। नशा मुक्ति के संदेश को हर घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत भरतपुर द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल प्रभावी रहा, बल्कि समाज को जागरूक व जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सराहा गया।

हवाई पट्टी पर रेत मंडी से बढ़ रही अव्यवस्था, मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिक परेशान, बड़ा हादसा होने का खतरा

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शहर की हवाई पट्टी के पास सुबह-सुबह लगने वाली अस्थायी रेत मंडी अब स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों का कहना है कि सुबह से ही रोड पर रेत से भरी गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे रास्ता जाम हो जाता है। हवाई पट्टी क्षेत्र लंबा और खुला होने के कारण यहाँ लोगों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है, लेकिन रेत मंडी की अव्यवस्थित पार्किंग ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।

नगर के जागरूक नागरिकों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मंडी के लिए पहले से निर्धारित व्यवस्थित स्थान मौजूद है, फिर भी कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और रेत व्यापारी जानबूझकर बीच सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। इससे न केवल जाम लगता है बल्कि हर किसी के लिए आने-जाने में असुविधा होती है।

ग्वालियर की घटना से बढ़ी चिंता: हाल ही में ग्वालियर में रेत की ट्रॉली में पीछे से फॉर्च्यूनर की टक्कर में पांच युवाओं की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। शिवपुरी के नागरिकों का कहना है कि यदि हवाई पट्टी क्षेत्र में जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो यहां भी किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

24 तारीख से बाबा बागेश्वर की कथा- बढ़ेगा यातायात दबाव: शिवपुरी हवाई पट्टी के पास आगामी 24 तारीख से बाबा बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन प्रस्तावित है। हजारों भक्तों के आने की संभावना है। ऐसे में मौजूदा अव्यवस्था और रेत मंडी का सड़क पर फैलाव किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को और बढ़ा रहा है। नागरिकों का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़, वाहनों का दबाव और रेत मंडी की अवैध पार्किंग एक साथ मिलकर गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं।

रतलाम में सब्जी विक्रेता सड़क पर बैठे, चक्का जाम किया

महापौर को बुलाने की मांग पर अड़े; नगर निगम की कार्रवाई का विरोध

रतलाम, एजेंसी। रतलाम में नगर निगम द्वारा सड़क के किनारे सब्जी विक्रेताओ को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार सुबह निगम की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों जाकर सब्जी, फल फरूट विक्रेताओं को हटाकर सामान जब्ती की कार्रवाई की।

कार्रवाई के विरोध में सभी फुटकर नगर निगम पहुंच गए। तीन घंटे बैठे रहने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर शाम 4 बजे नगर निगम के बाहर चक्काजाम कर दिया। महापौर प्रहलाद पटेल को बुलाने की मांग पर अड़ गए। दरअसल नगर निगम द्वारा चांदनी चौक, त्रिपोलिया गेट, नीम चौक क्षेत्र में सड़क किनारे सब्जी, फल फरूट और ठेला चालकों को हटाने की कार्रवाई की। सभी को अमृत सागर तालाब किनारे शिफ्ट करने की तैयारी है। लेकिन सब्जी विक्रेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। विक्रेताओं का कहना है कि रात के समय सब्जी लेने उस क्षेत्र कोई नहीं आएगा। वहां किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं। इसका असर हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा। सुबह नगर निगम की टीम ने 100 से 150 सब्जी विक्रेता को हटा दिया। सामान भी जप्त कर लिया।

11 बजे से नगर निगम में बैठे: सभी विक्रेता सुबह 11 बजे नगर निगम पहुंचे। लेकिन कोई भी अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया। दोपहर बाद सभी सड़क पर बैठ गए। चक्काजाम की सूचना पुलिस भी पहुंची। लेकिन निगम का कोई अधिकारी नहीं आया। बाद में नायब तहसीलदार रामचंद्र पांडे पहुंचे। समस्या सुनी। फिर वह निगम अधिकारियों के पास गए। लेकिन उन्हें भी कोई भी अधिकारी नहीं मिला।

सब्जी विक्रेताओं का आरोप-निगम वाले धमकी दे रहे: विक्रेताओं ने कहा कि हम गरीब सब्जीवाले सब्जी, फल का ठेला लगाकर अपना भरण पोषण करते है। अपने बच्चो का पालन करते है। मकान किराया लोन की किस्ते आदि भरते है। नगर निगम वाले धमकी दे रहे है कि आइंदा यहां पर गाडी लगाई तो तुम्हारी ठेलागाड़ी उठाकर ले जाएंगे।

किसान महासंघ का 1 दिसंबर को आगरा-मुंबई हाईवे पर आंदोलन, खरगोन में रूपरेखा बनी

खरगोन, एजेंसी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ 1 दिसंबर को आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खलघाट टोल के पास किसान आंदोलन करेगा। इस प्रदर्शन में निमाड़ क्षेत्र के चार जिलों के किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचेंगे। खरगोन जिले के बासवा और डोंगरगांव में जिला स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रतिनिधियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपने साथ आटा, दाल, दो जोड़ी कपड़े और पहले दिन के लिए दो समय का भोजन लेकर आएं। संगठन ने संकेत दिया है कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है। महासंघ की प्रमुख मांगों में किसानों की ऋण मुक्ति, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा कपास की खरीदी, मक्का खरीदी और गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करना शामिल है।

4 जिलों के किसान ट्रैक्टर से पहुंचेंगे

पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। अब किसानों के पास अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस आंदोलन में खरगोन, खंडवा, धार और बड़वानी जिलों के किसान शामिल होंगे। बड़वानी जिले के ठीकरी में भी पिछले सप्ताह एक बैठक आयोजित की गई थी।

सीहोर में पिता-पुत्र से मारपीट मामला

जाटव समाज में आक्रोश

सीहोर, एजेंसी। सीहोर जिला मुख्यालय पर बदमाशों ने एक टेंट कारोबारी युवक और उसके पिता से दो बार मारपीट की। दूसरी बार हमला जिला अस्पताल में उस समय किया गया, जब मौके पर पुलिस सिपाही भी मौजूद था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट प्रवेश परिहार और उनके पिता हरिसिंह परिहार के साथ हुई। अस्पताल में हमला करने वालों में दीपक परमार, भानु राठौर और नवीन राठौर शामिल थे। थाना कोतवाली पुलिस ने घटना पर दो अलग-अलग स्नढ्डक्र दर्ज की हैं। पुलिस ने दीपक परमार और नवीन राठौर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भानु राठौर अभी फरार है। उसकी तलाश जारी है।

जाटव समाज का विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग: इस घटना के विरोध में जाटव समाज के लोग स्क्क कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने फरार आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और मामले में धाराएं बढ़ाने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत को ज्ञापन सौंपा।

SP बोलीं- धाराएं बढ़ाई, तलाश जारी: एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने कहा कि मामले में धाराओं का इजाफा कर दिया गया है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सीएम हाउस जाकर धरना देंगे।

पन्ना में बेकाबू होकर पलटी बोलेरो, दो युवकों की मौत

एक गंभीर, करतल से अजयगढ़ जा रहे थे तीनों; संतराम ढाबे के पास हादसा

पन्ना, एजेंसी। पन्ना जिले के अजयगढ़ में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में बोलेरो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटी: अजयगढ़ थाना प्रभारी बखत सिंह ने बताया कि बोलेरो (यूपी-90यू6908) में तीन लोग सवार थे। इनमें नीरज यादव (28), अमित अवस्थी (31) और लल्लू राजपूत (30) शामिल थे। मंगलवार सुबह ये सभी करतल से अजयगढ़ की ओर आ रहे थे। इस दौरान संतराम ढाबे के पास उनकी बोलेरो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद घायलों को अजयगढ़ अस्पताल ले जाया गया। नीरज यादव और अमित अवस्थी को मृत घोषित कर दिया गया।

एक घायल जिला अस्पताल रेफर: वहीं गंभीर घायल लल्लू राजपूत को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में बोलेरो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। थाना प्रभारी बखत सिंह ने बताया कि घटना के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा।

खंडवा के खालवा कॉलेज के बाहर एबीवीपी का चक्काजाम

कार्यकर्ता बोलें- कॉलेज में पीने का पानी, बैठने की जगह तक नहीं

खंडवा, एजेंसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को खालवा कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर चक्काजाम कर दिया। विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। फिर रोड़ जाम कर दिया।

एबीवीपी ने यह मांगें रखी: शासकीय महाविद्यालय खालवा को उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए पीने योग्य पानी और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महाविद्यालय में स्थायी सफाईकर्मी नियुक्त किया जाए, ताकि स्वच्छता व्यवस्था नियमित बनी रहे। कॉलेज में स्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आ सके। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। तहसीलदार खालवा के नाम उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया हैं।

छतरपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक गिरा

घना कोहरा छाया, फसलों पर ओस की बूंदें दिखीं; किसानों को फसलों के लिए फायदा

छतरपुर,एजेंसी। छतरपुर में सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक ठंड ने तेज असर दिखाया। सुबह 7 बजे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर की बाहरी सीमाओं पर करीब 2 किलोमीटर तक घना कोहरा छाया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

वर्तमान में अधिकतम तापमान 25 डिग्री, हवा की गति 2 किमी/घंटा और नमी 51 प्रतिशत दर्ज की गई। रात का तापमान 12 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और दिन में आसमान साफ रहेगा।

किसानों को ठंड से फायदा मिलने की उम्मीद: ठंड बढ़ने से किसानों को फसलों के लिए लाभ मिलने की संभावना है। जिले में गेहूं, ज्वार, लाहा, चना और मटर की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह फसलों पर ओस की बूंदें देखी जा रही हैं, जिन्हें पैदावार के लिए लाभकारी माना गया है। ठंड के कारण लोग सुबह, शाम और रात में गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। मफलर, जैकेट और दस्ताने पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही गर्म भोजन और पेय पदार्थों का सेवन बढ़ गया है।

नौगांव और खजुराहो में अधिक ठंड: नौगांव और खजुराहो में ठंड का असर ज्यादा देखा गया। नौगांव में कुछ दिन पहले तापमान 1 डिग्री तक दर्ज हुआ। इन क्षेत्रों में अधिक ठंड का कारण भौगोलिक संरचना, ग्रेनाइट की चट्टानें और अक्षांशीय स्थिति मानी जा रही है। हिमालय से आने वाली उत्तरी-पूर्वी हवाएं सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, पौष्टिक भोजन और गर्म पेय पदार्थ लें। सुबह की धूप में बैठें, हल्का व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें।

कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे गुजारी रात, नर्मदापुरम में आशा कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, 24 घंटे के धरने में

नर्मदापुरम, एजेंसी। नर्मदापुरम में आशा, ऊषा और सुपरवाइजर मातृ शक्तियों ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे का धरना शुरू किया है। इनकी मुख्य मांगें 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है। सोमवार सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट के पास शुरू हुआ यह धरना मंगलवार (आज) 11 बजे तक चलेगा। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद 27 मातृ शक्तियां पूरी रात खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठी रहीं। सोमवार को जिलेभर से 100 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर इस धरने में शामिल हुईं। इनमें से 27 महिलाएं रात में भी कड़कड़ाती ठंड में डटी रहीं। कई महिलाएं कंबल, रजाई ओढ़कर तो किसी ने अलाव जलाकर रात गुजारी। इनकी सुरक्षा के लिए कोतवाली थाने की दो महिला पुलिस कर्मी भी रात भर मौके पर तैनात रहीं।

बंधुआ मजदूर जैसा काम, दिवाली पर भी नहीं मिला वेतन: आशा कार्यकर्ता ममता तिलोटे ने कहा कि सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम समय पर काम पूरा करें, लेकिन हमारी भी उम्मीद है कि हमारे काम का मानदेय और वेतन समय पर मिले। उन्होंने कहा, कई बार ऐसा लगता है जैसे हमसे बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है।÷

4 महीने से अटका है पैसा: ममता तिलोटे ने बताया कि सरकारी और निजी संस्थानों में मजदूरों को बोनस मिला, लेकिन हम आशा कार्यकर्ताओं को न तो बोनस मिला और न ही इंसेंटिव। हमारी मेहनत का पैसा भी चार महीने से अटका हुआ है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी हमें वेतन नहीं मिला, जिस वजह से त्योहार बहुत साधारण तरीके से मनाना पड़ा।

26 हजार वेतन और कर्मचारी का दर्जा चाहिए: आशा ऊषा सुपरवाइजर एकता यूनियन (सीटू) की जिला अध्यक्ष बबीता चौबे ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि आशा, ऊषा कार्यकर्ता और सुपरवाइजर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनका वेतन 26 हजार रुपये किया जाए। इसी मांग को लेकर जिलेभर की बहनें 24 घंटे के धरने पर बैठी हैं।

आज रैली निकालकर सौंपेंगी ज्ञापन: सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ 24 घंटे का धरना मंगलवार (आज) 11 बजे समाप्त होगा। धरना समाप्त करने से पहले सभी कार्यकर्ताएं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेंगी। बबीता चौबे ने कहा कि धरना खत्म होगा, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी।

मंदसौर के डिगांव में बाड़े में आग, दो गायें झुलसीं

एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया

मंदसौर, एजेंसी। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के डिगांव गांव में मंगलवार सुबह एक किसान के बाड़े में अचानक आग लग गई। लपटें उठते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू किया। घटना नानू पिता नन्दा बागरी के बाड़े में हुई। आग में उनकी दो गायें झुलसकर घायल हो गई। ग्रामीणों ने पानी के टैंकर की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। झुलसी गायों का उपचार कराया जा रहा है।

घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जानकारी में आग कैसे भड़की, यह स्पष्ट नहीं है। अफजलपुर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह कनेश के अनुसार सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस आगजनी के कारणों की जांच कर रही है।

टीकमगढ़ में ग्रामीणों का प्रदर्शन, अवैध कब्जे हटाने की मांग

गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते पर अतिक्रमण, एसडीएम को दिया ज्ञापन

टीकमगढ़, एजेंसी। टीकमगढ़ में नगर परिषद कारी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर एसडीएम संस्कृति लिटोरिया को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों की बात सुनी और मौके का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। कारी निवासी प्रेमलाल कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा ने बताया कि नगर परिषद कारी में गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और गोपालपुरा भाटा से होकर गुजरता है।

अवैध कब्जे के कारण किसान और वार्डवासियों का आवागमन बाधित हो गया है। दिनरया यादव और लछिया अहिरवार के खेत के बगल से गुजरने वाला एक पगडंडी रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10 के लिए नगर परिषद द्वारा निर्मित श्मशान और कॉम्प्लेक्स शौचालय पर भी भू-माफिया ने कब्जा कर गेहूं की फसल बो दी है। ग्रामीणों ने एसडीएम से तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाने और पटवारी से मौके का निरीक्षण कराकर आम रास्ता खुलवाने की मांग की। एसडीएम ने तहसीलदार को मौके पर बुलाया और निरीक्षण के निर्देश देते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

सागर में ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या

सागर, एजेंसी। सागर के कैंट थाना क्षेत्र के भगवानगंज स्टेशन रोड पर सोमवार रात एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय दीपचंद साहू निवासी अंबेडकर वार्ड के रूप में हुई है, जो एक शिक्षिका का ड्राइवर था। दुखद बात यह है कि आज (18 नवंबर) को उसकी गोद भराई की रस्म थी और 4 दिसंबर को उसकी शादी होनी थी। पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतक दीपचंद साहू भैसवाही गिरवर के स्कूल में पदस्थ एक शिक्षिका का ड्राइवर था। वह कार चलाता था। सोमवार की शाम वह कार लेकर भगवानगंज स्थित एक कार पार्लर पर कार का काम कराने पहुंचा था।

कार का काम शिक्षिका देख रही थीं। तभी ड्राइवर दीपचंद कार पार्लर से बाहर आया। इसी दौरान बाइक सवार नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने दीपचंद पर चाकू से हमला कर दिया। घटना देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दीपचंद को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने दीपचंद को मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।

आज थी गोद भराई, 4 दिसंबर को थी शादी: मृतक के भाई संतोष साहू ने बताया कि हम लोग तीन भाई थे और दीपचंद सबसे छोटा भाई था। उसकी शादी होने वाली थी। आज (18 नवंबर) को लड़की के घर गोद भराई की रस्म के लिए जाने वाले थे और 4 दिसंबर को उसकी शादी थी। भाई ने बताया कि शादी की तैयारियां घर में चल रही थीं। कार्ड छप चुके थे। रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए थे। गोद भराई की रस्म के लिए तैयारी पूरी हो चुकी थी। सुबह बिचपुरी परिवार के लोग जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह वारदात हो गई।

पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज: संतोष साहू ने बताया कि वारदात किसने और क्यों की, यह स्पष्ट पता नहीं है। लेकिन करीब दो माह पहले भाई (दीपचंद) का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। वारदात सामने आते ही कैंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आए हैं।

एएसपी बोले- जल्द पकड़ेंगे आरोपी: एडिशनल एसपी लोकेश सिंहा ने बताया कि युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। मृतक पेशे से ड्राइवर था।

दीपचंद साहू, मृतक

रायसेन में अलाव की चिंगारी से टपरा जलकर खाक :70 वर्षीय सोता बुजुर्ग बुरी तरह झुलसा, परिजन पहुंचे तब तक चली गई जान

रायसेन,एजेंसी। रायसेन में सर्दी से बचने के लिए जलाए गए अलाव से एक टपरे में आग लग गई। इस घटना में टपरे में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह घटना सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11 बजे सलामतपुर थाना क्षेत्र की भगवंतपुर कॉलोनी में हुई। जानकारी के अनुसार, शव की पहचान प्यारेलाल पिता खुमान सिंह (70) के रूप में हुई है। अलाव की चिंगारी से टपरे में आग लग गई, जिससे प्यारेलाल गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने पर बुजुर्ग ने चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद पास के घर से निकल कर परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, तब तक बुजुर्ग बुरी तरह झुलस चुके थे और कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सलामतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

विकेट को दोष देना आसान, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना होगा : अमित मिश्रा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच को 30 रन के करीबी अंतर से गंवा बैठी। पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा का मानना है कि इसके लिए विकेट को दोष देना आसान है, लेकिन खिलाड़ियों को अपने गिरेबान में झांकना होगा। भारत-साउथ अफ्रीका के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए इस टेस्ट मैच में टेंबा बावुमा ऐसे इकलौते बल्लेबाज रहे, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए सिर्फ 124 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम इंडिया 93 रन पर सिमट गई। इसके बाद कुछ दिग्गजों ने इस शर्मनाक हार के लिए पिच को दोषी ठहराया। अमित मिश्रा ने आईएएनएस से कहा, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की विकेट मिली हो। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स निखारनी होगी। अपनी स्किल्स को सुधारने की जरूरत है। विकेट को दोष देना आसान है, लेकिन इससे पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। जब हम इंग्लैंड जैसे देशों का दौरा करते हैं, तो वहां स्विंग का सामना करना पड़ता है। हम उस हिसाब से अपनी स्किल्स को सुधारते हैं। आपको समझना होगा कि किस तरह की पिच पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी।

उन्होंने कहा, यह एक युवा टीम है। इसमें काफी युवा खिलाड़ी हैं, जिनमें अनुभव की कमी है। सीनियर खिलाड़ियों और कोच को उनसे बात करनी होगी। इस तरह की पिच पर फुट मूवमेंट बेहद अहम है। आपको यह समझना होगा कि किन गेंदबाजों के खिलाफ शॉट खेल सकते हैं, किन गेंदबाजों के खिलाफ शॉट नहीं खेलने। यह सभी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। भविष्य में यह टीम बेहतरीन हो जाएगी। साउथ अफ्रीका ने मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की।

दूसरी पारी में भी साउथ अफ्रीकी टीम की हालत खराब रही, लेकिन कप्तान टेंबा बावुमा की नाबाद 55 रन की पारी के दम पर टीम ने किसी तरह 153 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य दिया। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 93 के स्कोर तक अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी। चोटिल कप्तान शुभमन गिल इस पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके। इसी के साथ टीम इंडिया को सीरीज के पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा।

जर्मनी और नीदरलैंड ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया

नई दिल्ली, एजेंसी। स्लोवाकिया को 6-0 से शिकस्त देकर जर्मनी ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यूरोपीय दिग्गजों के साथ नीदरलैंड्स भी विश्व कप में जगह पक्की कर चुका है, जिसने लिथुआनिया को 4-0 से हराते हुए ग्रुप जी में पहला स्थान हासिल किया। लेरॉय साने जर्मनी की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने स्लोवाकिया के खिलाफ दो गोल दागते हुए जर्मनी को लगातार 19वें विश्व कप में जगह दिलाई। निक वोल्टेमाडे ने इस मुकाबले का खाता खोला। 18वें मिनट उन्होंने हेडर से गोल दागा, जिसके बाद सर्ज ग्नब्री ने 29वें मिनट गोल करते हुए जर्मनी की बढ़त को दोगुना कर दिया।

यहां से फ्लोरियन विर्ट्ज ने लेरॉय साने को 5 मिनट में दो बार गोल करने का मौका दिया और हाफ टाइम से पहले मैच को सुरक्षित बना दिया। लेरॉय ने बखूबी इन मौकों को भुनाते हुए 36वें और 41वें मिनट में दो गोल करते हुए जर्मनी को 4-0 से बढ़त दिला दी।

ब्रेक के बाद रिडल बाकू ने 67वें मिनट में गोल किया। मुकाबले के 79वें मिनट असन ओउएड्राओगो ने साने के शानदार शॉट के बाद गोल दागकर टीम को 6-0 से आगे कर दिया। मुकाबला इसी स्कोर के साथ खत्म हुआ।

दूसरी ओर, ग्रुप-जी के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने लिथुआनिया पर 4-0 से जीत दर्ज करते हुए विश्व कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। मुकाबले के 16वें मिनट तिजानी रेंडर्स ने दाहिने पैर से गोल करते हुए नीदरलैंड्स का खाता खोला।

माइकल वॉन की भविष्यवाणी, 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी एशेज सीरीज

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होने जा रही है। इस सीरीज में पांच मुकाबले खेले जाने हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है कि एशेज सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म होगी, जबकि एक मैच ड्रॉ रहेगा। माइकल वॉन का कहना है कि बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम पर्थ में सीरीज के पहले मैच में जीत हासिल करेगी, जिसकी वजह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस और जोश हेजलवुड का इस मैच से बाहर होना है। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर बेन स्टोक्स फिट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सीरीज 2-2 से बराबर रहेगी। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पैट या जोश की गैरमौजूदगी में जीतेगी। अगर सीरीज के पहले टेस्ट से पूर्व

कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होता, तो यही मेरी आखिरी भविष्यवाणी है।

पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज हेजलवुड को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान विक्टोरिया के खिलाफ न्यू साउथ वेल्स की ओर से खेलते हुए हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई। शनिवार को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि जोश हेजलवुड के बाहर होने के बाद, एशेज के पहले मैच में मेहमान इंग्लैंड की स्थिति बेहतर है।

वॉन ने कहा था, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेजलवुड और कमिंस पहले टेस्ट से बाहर हैं। यह शुरुआती संकेत हैं कि बड़ी सीरीज जीतने के लिए जरूरी तेज गेंदबाजी इंग्लैंड के पक्ष में जा रही है। पर्थ में उनके लिए एक अंक आगे जाने का बड़ा मौका है। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिचेल स्टार्क एकमात्र पूरी तरह से फिट पहली पसंद के तेज गेंदबाज हैं, जबकि स्कॉट बोलैंड बैकअप खिलाड़ी के रूप में हैं। हेजलवुड के चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर को तेज गेंदबाज के रूप में मौका देने पर पर विचार कर सकता है।

कमिंस, एबॉट और हेजलवुड के चोटिल होने के कारण, अनकैप्ड तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, जिन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए दो बार पारी में 5 विकेट हासिल किए हैं।

बतौर हेड कोच राजस्थान रॉयल्स में कुमार संगकारा की वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के रूप में श्रीलंकाई दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा की टीम में वापसी हुई है। इसी के साथ संगकारा क्रिकेट निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे। इस बीच फ्रेंचाइजी ने विक्रम राठौर को मुख्य सहायक कोच के पद पर पदोन्नत किया है, जबकि शेन बॉन्ड गेंदबाजी कोच बने रहेंगे। इनके अलावा, ट्रेवर पेनी सहायक कोच और सिड लाहिड़ी प्रदर्शन कोच के रूप में वापसी करेंगे। संगकारा की नियुक्ति को लेकर फ्रेंचाइजी के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने कहा, जब हमने विचार किया कि इस समय टीम को क्या चाहिए, तो हमें लगा कि टीम के साथ उनकी सहजता, उनका नेतृत्व और रॉयल्स के कल्चर की उनकी गहरी समझ निरंतरता और स्थिरता का सही संतुलन लाएगी।

उन्होंने कहा, एक लीडर के रूप में हमें कुमार (संगकारा) पर हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, धैर्य और क्रिकेट की

समझ टीम को अगले चरण में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुमार संगकारा इससे पहले साल 2021 से 2024 के बीच टीम के हेड कोच के रूप में कार्यरत थे। उनके मार्गदर्शन में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 का फाइनल खेलने के बाद आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाई थी। इसके बाद आईपीएल 2025 में राहुल द्रविड़ ने यह पद संभाला, लेकिन एक ही सीजन के बाद ही द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया।

आईपीएल 2025 में राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। यह टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में नौवें पायदान पर रही। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में अब तक सिर्फ एक बार खिताब अपने नाम किया है। इस टीम ने साल 2008 में आईपीएल इतिहास का पहला सीजन जीता था, जिसके बाद साल 2022 के फाइनल में पहुंचकर उसे गुजरात टाइटंस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

मैं मरने के लिए तैयार हूं

युवराज के पिता योगराज सिंह का चौंकाने वाला बयान, कहा- खाने को भी दूसरों पर निर्भर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं। उन्हें कई बार धोनी पर युवराज का करियर समाप्त करने का आरोप लगाते देखा गया है। इस बार पूर्व क्रिकेटर योगराज ने अपने निजी जीवन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनका जीवन पूरा हो चुका है और वह मरने के लिए तैयार हैं।

खाने को अजनबियों पर रहना पड़ता है निर्भर: विंटेज स्टूडियो को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज ने कहा कि उन्हें खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा, मैं शाम को अकेला बैठा रहता हूं, घर पर कोई नहीं होता। खाने के लिए मैं अजनबियों पर निर्भर रहता हूं, कभी एक, कभी दूसरा। हालांकि, मैं किसी को परेशान नहीं करता। अगर मुझे भूख लगती है तो कोई न कोई मेरे लिए खाना ले आता है। मैंने घर में नौकर और रसोइये रखे हैं, वे खाना परोसकर चले जाते हैं।

परिवार से बहुत प्यार करता हूं: इस दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी से सहायता नहीं मांगते। योगराज ने आगे कहा, मैं अपनी मां, बच्चों, बहू, नाती-पोतों, परिवार के सभी लोगों से प्यार करता हूं। लेकिन, मैं कुछ नहीं मांगता। मैं मरने को तैयार हूं। मेरा जीवन पूरा हो गया है, भगवान जब चाहें, मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं भगवान का बहुत आभारी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं और वह देते रहते हैं।

पत्नी और बेटे के अलग होने का योगराज को है मलाल: 62 वर्षीय योगराज ने बताया कि उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनकी पत्नी और बेटे युवराज ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। योगराज ने कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जब हालात ऐसे हो गए कि युवी और उसकी मां मुझे छोड़कर चले गए, तो मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। जिस औरत के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं इस तरह बहुत सी चीजें बर्बाद हो गईं। मैंने भगवान से पूछा कि जब मैंने सबके साथ सब कुछ सही किया, तो ये सब क्यों हो रहा है। हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की हों, लेकिन मैं एक निर्दोष इंसान हूं, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं भगवान के सामने रोया।

महिला टी-20 विश्वकप फॉर द ब्लाइंड

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच दिखी खेलभावना, खिलाड़ियों ने मैच के बाद मिलाया हाथ

कोलंबो ,एजेंसी। महिला टी20 विश्व कप फॉर द ब्लाइंड में 16 नवंबर को भारत और पाकिस्तान की खिलाड़ी मैदान पर भिड़ीं, लेकिन मैच के बाद उन्होंने जो किया, उसने सभी का ध्यान खींच लिया। श्रीलंका के कटुनायके स्थित बीओआई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले के बाद दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। यह इसलिए खास रहा क्योंकि हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच कई टूर्नामेंट्स में नो-हैंडशेक पॉलिसी चल रही थी। एशिया कप से शुरू हुआ यह ट्रेंड पुरुष टीमों तक पहुंचा था, जहां सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया और सलमान आगा की पाकिस्तान टीम ने भी हैंडशेक नहीं किया था। यही सिलसिला महिला वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप तक जारी रहा, लेकिन इस मैच ने उस दूरी को पलों में मिटा दिया। जानकारी के अनुसार, दोनों टीमें एक ही बस से स्टेडियम पहुंचीं और मैच के बाद भी एक-दूसरे को बधाई दी।

नाओमी ओसाका ने ऑकलैंड डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट से नाम वापस लिया

अब यूनाइटेड कप में जापान के लिए खेलेंगी

वेलिंगटन, एजेंसी। चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका ने जनवरी में होने वाले ऑकलैंड के एएसबी क्लासिक डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। ओसाका अब न्यूज़ीलैंड के बजाय ऑस्ट्रेलिया में होने वाले यूनाइटेड कप 2026 में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओसाका ने सितंबर में घोषणा की थी कि वह अपनी 2026 सीज़न की शुरुआत ऑकलैंड से करेंगी, जहाँ उन्होंने इस साल की शुरुआत में फाइनल तक पहुंचकर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब उन्होंने टूर्नामेंट निदेशक निकोलस लैम्पेरिन को सूचित किया कि वह अपना प्री-ऑस्ट्रेलियन ओपन तैयारी चरण

ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू करना चाहती हैं।

यूनाइटेड कप में ओसाका जापान की टीम में शिंटारो मोचिज़ुकी के साथ खेलेंगी। टूर्नामेंट 2 से 11 जनवरी तक पर्थ में होगा, और ग्रुप स्टेज में जापान का सामना ब्रिटेन और ग्रीस से होगा। गौरतलब है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से मेलबर्न पार्क में शुरू होगा।

नीतीश रेड्डी की दूसरे टेस्ट से पहले टीम में वापसी

कोलकाता टेस्ट से पहले हुए थे रिलीज; कप्तान गिल की फिटनेस पर संशय

मुंबई, एजेंसी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में वापस बुला लिया गया है। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। रेड्डी को दो मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन कोलकाता में हुए पहले टेस्ट से ठीक पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया और भारत-ए की साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ सीरीज के लिए भेज दिया गया था। BCCI पहले ही साफ कर चुका था कि वे दूसरे टेस्ट से स्क्वॉड में जुड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें निर्धारित समय से पहले बुला लिया गया है। पहले टेस्ट में भारत हारा, मैच ढाई दिन में ही खत्म पहला टेस्ट ईडन गार्डन्स में खेला गया था, जो ढाई दिन में ही खत्म हो गया। भारत को इस मैच में 30 रन से हार झेलनी पड़ी। 14 नवंबर से शुरू हुआ मुकाबला 16 नवंबर की दोपहर में

ही समाप्त हो गया, जबकि इसे 18 नवंबर तक खेला जाना था। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 और दूसरी पारी में 153 रन बनाए। जवाब में भारत ने पहली पारी में 189 रन और दूसरी पारी में केवल 93 रन बनाए।

रेड्डी ने साउथ ए के खिलाफ पहले मुकाबले में 37 रन बनाए थे राजकोट में पहले भारत-ए मैच में रेड्डी ने 37 रन बनाए और गेंदबाजी में 1/18 का स्पैल डाला। दूसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मौका नहीं मिला। अब स्क्वाड में वापसी के कारण वे 19 नवंबर को होने वाला तीसरा भारत-ए मैच नहीं खेल पाएंगे। गिल की फिटनेस पर संशय, रेड्डी हो सकते हैं महत्वपूर्ण विकल्प कप्तान शुभमन गिल की गर्दन की चोट से उबरने में देरी हो रही है और उनका दूसरे टेस्ट में खेलना अभी भी संशय में है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को एक अतिरिक्त बल्लेबाजी कवर की जरूरत पड़ सकती है। भारत के पास देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन दोनों लेफ्ट-हैंडर हैं और टीम में पहले से ही कई लेफ्ट-हैंडर बल्लेबाज मौजूद हैं। इससे मैच-अप में समस्या आ सकती है।

ऐसे में नितीश रेड्डी टीम को बेहतर संतुलन दे सकते हैं। वे नीचे के क्रम में बैटिंग करके लेफ्ट-राइट संयोजन बनाए रखने में मदद करेंगे। गुवाहाटी में पहला टेस्ट, भारत को वापसी की उम्मीद कोलकाता टेस्ट ढाई दिनों में खत्म हो गया था और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। अब सबकी निगाहें गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट पर होंगी, जो इस मैदान का पहला टेस्ट मैच होगा।

शमी को टीम में वापस लाओ, पहले टेस्ट में हार के बाद इस पूर्व कप्तान ने कोच गंभीर को दी सलाह

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुख्य कोच गौतम गंभीर को सलाह दी है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद टीम और कोच गंभीर की आलोचना की जा रही है। गांगुली ने अब कोच को सलाह देते हुए कहा है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल करना चाहिए।

15 साल में पहली बार अपनी ही धरती पर दक्षिण अफ्रीका से हारा भारत: भारतीय टीम ने पहली पारी में 30 रनों की बढ़त ली थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजों के दम पर वापसी की और भारत को हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर ऑलआउट हुई थी और उसने 123 रनों की

बढ़त लेकर भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 साल में पहली बार भारत को घरेलू जमीन पर टेस्ट मैच गंवाना पड़ा।

शमी को नहीं चुने जाने पर हुआ था विवाद: शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। शमी आखिरी बार भारत के लिए 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में लाल गेंद के प्रारूप में खेले थे। इसके बाद से वह टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सके हैं। उन्हें इंग्लैंड दौरे और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया था। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कहना था कि फिटनेस के कारण शमी का चयन नहीं किया गया है। गांगुली ने कहा कि गंभीर को शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी तिकड़ी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शमी और स्पिनर मिलकर भारत को टेस्ट मैच जीता सकते हैं। गांगुली ने एक चैनल से कहा, मुझे गौतम बहुत पसंद हैं, उन्होंने 2011 और टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह कुछ समय तक ऐसा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें भारत की अच्छी पिचों पर खेलना होगा। उन्हें बुमराह, सिराज और शमी पर भरोसा रखना होगा। मुझे लगता है कि शमी भारतीय टीम में जगह बनाने के हकदार हैं। शमी और स्पिनर टेस्ट में जीत दिला सकते हैं।

गांगुली बोले- मैच खत्म करने की जल्दी नहीं करें गंभीर: घरेलू क्रिकेट में वापसी के बाद से शमी शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। उन्होंने चार मैचों में 17.35 के औसत से 17 विकेट लिए हैं। गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर और भारतीय टीम प्रबंधन को अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए और पिच को खेल से दूर रखना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान ने कोच से यह भी कहा कि उन्हें मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश करने के बजाय पांच दिन में टेस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए। गांगुली ने कहा, अच्छे विकेटों पर खेलो। उम्मीद है गौतम गंभीर सुन रहे होंगे। उन्हें खेल से पिच को दूर रखना होगा क्योंकि अगर उनके बल्लेबाज 350-400 रन नहीं बना पाएंगे, तो वे टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे।

विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत 7 जनवरी से होगी

मुंबई में लीग मैच, बड़ौदा में फाइनल खेला जा सकता है; 27 नवंबर को मेगा ऑक्शन

मुंबई, एजेंसी। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। क्रिकबज के अनुसार, टूर्नामेंट के शुरुआती लीग मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जा सकते हैं, जिसने हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी की थी। बाकी मैचों के लिए बड़ौदा को चुना गया है, जिसमें कोटांबी स्टेडियम में होने वाला फाइनल भी शामिल है। बड़ौदा में मुकाबले 16 जनवरी से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इसी मैदान पर 11 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड का वनडे मैच खेलना है। टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन इसी महीने 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। पिछले सीजन में 4 शहरों ने की थी मेजबानी WPL के तीसरे सीजन की मेजबानी 4 शहरों ने की थी। इनमें लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा शामिल थे।

BCCI ने अभी फ्रेंचाइजी मालिकों को आधिकारिक रूप से नहीं बताया है कि इस बार मैच किस शहर में होंगे, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में इन्हीं वेन्यूज पर चर्चा चल रही है। टीमों को औपचारिक जानकारी 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाली WPL नीलामी के दौरान दी जा सकती है। इस बार भी मेजबानी के लिए वहीं 4 शहर- लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा ने दावेदारी पेश की थी। जिसमें मुंबई और बड़ौदा चुने गए हैं।

मतदाता सत्यापन मे लापरवाही पड़ी भारी, कलेक्टर ने बीएलओ को दिया निलंबन का आदेश

कलेक्टर ने कई मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर गहन पुनरीक्षण कार्य का लिया जायजा

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। जिले भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता के सत्यापन के लिए गणना पत्रक घर–घर जाकर वितरित कर दिए गए हैं। अब बीएलओ तथा अन्य कर्मचारी गणना पत्रक मतदाता से प्राप्त करके उसका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने रीवा विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों का भ्रमण करके मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर ने नेहरू नगर में सामुदायिक भवन मतदान केंद्र क्रमांक 82 के निरीक्षण के दौरान बीएलओ मधु गुप्ता से जानकारी ली। बीएलओ द्वारा गणना पत्रक के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। मौके पर उपस्थित कई मतदाताओं ने बीएलओ द्वारा कार्य न करने तथा गणना पत्रक वितरित न करने की शिकायत की। कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए बीएलओ को निलंबित करने के आदेश दिए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मतदाताओं के सत्यापन का कार्य तय समय सीमा में पूरा करें। इसके बाद कलेक्टर ने पीके स्कूल के समीप जोन क्रमांक तीन में एसआईआर हेल्प डेस्क सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने गणना पत्रक भरे जाने तथा डिजिटाइजेशन की जानकारी ली। निरीक्षण के समय एसडीएम हुजूर डॉ अनुराग तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर बेक, नायब तहसीलदार तेजपति सिंह तथा अन्य कर्मचारी एवं मतदाता उपस्थित रहे।

लोकतंत्र में निरंकुश शासक को बदलने के लिए विधान सभा एवं लोकसभा का चुनाव अलग-अलग समय में किया जाना आवश्यक: बुद्धसेन पटेल

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच, मध्यप्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग–अलग समय पर कराए जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित है, जहां अलग–अलग भाषाएं, रहन–सहन और क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। यही कारण है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती हैं और केन्द्र सरकार को भी अनेक क्षेत्रीय दलों के सहयोग से चलाना पड़ता है, जिसके कारण केन्द्र की सत्ता निरंकुश नहीं हो पाती और लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है।

पटेल ने कहा कि यदि पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो सत्ता में मौजूद केन्द्र सरकार को सभी राज्यों में योजनाओं और आर्थिक सहायता के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का अवसर मिल जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में कई राज्यों में महिलाओं के सशक्तीकरण या अन्य योजनाओं के नाम पर 1500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक सीधे खातों में जमा कर राजनीति को प्रभावित करने की कोशिशें देखी जा रही हैं, जो लोकतंत्र और चुनाव आचार संहिता दोनों के लिए घातक हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग–अलग समय पर होने से मतदाताओं को सरकार बदलने का अवसर मिलता है और क्षेत्रीय दल भी जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को बार–बार जनता के बीच जाना पड़ता है, जिससे उन पर सुधार का दबाव बना रहता है।

मास्टर पटेल ने भारत सरकार से यह भी अपील की कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनावों की अवधि पाँच वर्ष की बजाय ढाई वर्ष की की जाए, ताकि आम मतदाता को अपने प्रतिनिधि को जल्दी बदलने या पुनः चुनने का अधिकार मिल सके। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से एक स्वस्थ, संवैधानिक और जवाबदेह लोकतंत्र की स्थापना सुनिश्चित होगी।

बीएलओ पर्यवेक्षक नियुक्त

रीवा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तीन विधानसभा क्षेत्रों बीएलओ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य में गणना पत्रकों के संग्रहण, डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति बढ़ाने और अनुवीक्षण के उद्देश्य से बीएलओ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

दो सीडीपीओ और दो बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने गूगल मीट के माध्यम से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से लेने और शत–प्रतिशत त्रुटिरहित सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह पुनरीक्षण कार्य जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि बीएलओ साथ–साथ इस कार्य में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, महिला एवं बाल विकास विभाग और राजस्व विभाग की टीम भी सहयोग कर रही है। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि कुछ क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। कार्य की गंभीरता को देखते हुए और कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने तत्काल संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मनगवां और जवा के बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा सिरमौर और जवा के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य को निर्धारित समय–सीमा और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूर्ण करें। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर पुनरीक्षण अभियान में सक्रियता लाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का सत्यापन छूटने न पाए।

6 फर्जी नियुक्ति के आरोपी पूर्व डीईओ को मिला प्रमोशन, कमिश्नर से हुई शिकायत; 15 दिन में हटाने का मिला आश्वासन, धरना स्थगित

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में घिरे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता को सहायक संचालक बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर बी.एस. जामोद से मुलाकात कर उन्हें पद से हटाने की मांग की। कमिश्नर से 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद 12 नवंबर से चल रहा धरना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, रीवा में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता के हस्ताक्षर से 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मामले में 7 लोगों पर थाने में 420 का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें पूरी तरह से माता–पिता को कागजों में मृत बताकर नौकरी पाई गई थी, जबकि उनके माता–पिता कभी विभाग में पदस्थ ही नहीं थे।

'छोटी मछलियों पर कार्रवाई, बड़े को प्रमोशन': सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि 6 फर्जी अनुकंपा नियुक्ति करने के बाद भी उन्हें प्रमोशन दिया गया है। जबकि यह अनुकंपा नियुक्तियां उनके ही द्वारा की गईं। लेकिन कार्यवाही केवल छोटी मछलियों पर की गई। जब निलंबित किया ही गया था तो संपत्ति और अन्य चीजों की जांच होनी थी, न कि प्रमोशन दिया जाना चाहिए था। इससे अन्य भ्रष्टाचारियों को क्या संदेश मिलेगा।

12 नवंबर से चल रहा था धरना: देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के बैनर तले कमिश्नर कार्यालय के सामने 12 नवंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसे सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह फैसला संगठन के प्रतिनिधि मंडल की रीवा संभाग के कमिश्नर बी.एस. जामोद से मुलाकात के बाद लिया गया।

आधे घंटे चली बैठक में उठे कई मुद्दे: बैठक में संगठन के संरक्षक विपिन कुमार सिंह, वरिष्ठ मार्गदर्शक सुभाष श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहयोगी रामेश्वर गुप्ता, उमाकांत पांडे, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, प्रिंस पांडे, राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, शिवानंद द्विवेदी सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। आधे घंटे चली बैठक में कई सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई।

15 दिन में हटाने का मिला आश्वासन: कमिश्नर ने संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में यह बात प्रमुख रही कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में विभागीय जांच का सामना कर रहे और सहायक संचालक के पद पर पदस्थ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता को पद से हटाने की प्रक्रिया तय समय–सीमा में पूरी की जाएगी।

'कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन': अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन पुनः आंदोलन एवं ज्ञापन की रणनीति अपनाएगा।

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण , अब तक 260065 गणना पत्रक हुए डिजिटाइज्ड

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। मतदाता के सत्यापन के लिए गणना पत्रक का शत–प्रतिशत वितरण कर दिया गया है। अब सभी बीएलओ घर–घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाकर उसे संकलित कर रहे हैं। इन्हें संकलित करके बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किया जा रहा है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 18 नवम्बर को शाम 6 बजे तक मतदाताओं से 260065 गणना पत्रक प्राप्त कर इसे डिजिटाइज कर लिया गया है। बीएलओ घर–घर जाकर गणना पत्रक संकलित कर रहे हैं। अब तक विधानसभा क्षेत्र गुढ़ में 32639, मनगवां में 43297, रीवा में 42970, सेमरिया में 47613, सिरमौर में 45811 तथा विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में 47735 गणना पत्रक डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मतदाताओं से बड़ी संख्या में गणना पत्रक प्राप्त हो गए हैं। इन्हें डिजिटाइज करने के लिए पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक तथा अन्य तकनीकी कर्मचारी बीएलओ को लगातार सहयोग कर रहे हैं। सभी गणना पत्रक 20 नवम्बर तक शत–प्रतिशत डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में गणना पत्रक भरवाने और संकलित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले भर में गणना पत्रक भरवाने के लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं।

डीपीएस ग्रुप का चार दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण संपन्न, छात्रों ने ग्वालियर; खजुराहो सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का किया अवलोकन

मीडिया ऑडिटर, मऊगंज (निप्र)। नईगढ़ी के डीपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने इस वर्ष भी विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से चार दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण यात्रा का आयोजन किया। लगभग 90 सदस्यों का दल 13 नवंबर की शाम विद्यालय परिसर से रवाना होकर 18 नवंबर को वापस लौटा। इस दौरान दल ने ग्वालियर, दतिया, बागेश्वर धाम, खजुराहो और पन्ना के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया। संचालक एडआरडी. शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों में अनुभव बढ़ता है, उनकी सोच विकसित होती है और उन्हें जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस यात्रा के दौरान छात्रों ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता, विज्ञान एवं गणित उन्मुखी प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली, ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों के प्रति व्यापक जानकारी हासिल की। यह अनुभव उन्हें पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया को समझने का अवसर प्रदान करता है।

आईटीआई में प्लेसमेंट ड्राइव 20 नवम्बर को

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। शासकीय आईटीआई रीवा में 20 नवम्बर को सुबह 9 बजे से प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। आईटीआई के प्राचार्य ने बताया कि होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कोलार कर्नाटक द्वारा असेंबली आपरेटर क्वालिटी इंस्पेक्टर पद के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। संस्था द्वारा संबंधित पद के लिए प्रशिक्षणार्थी का चयन किए जाने पर उसे 18525 रुपए मानदेय और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें 18 से 23 वर्ष की आयु के सभी आईटीआई पास प्रशिक्षणार्थी महिला एवं पुरूष भाग ले सकते हैं।

मॉडिफाइड वाहनों पर सख्ती, परिवहन विभाग ने जप्त किए वाहन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर रीवा के आदेशानुसार जिले में अवैध रूप से मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सिरमौर चौराहा और टीआरएस कॉलेज चौराहा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान चार मॉडिफाइड चार पहिया वाहनों को मौके पर ही जप्त कर लिया गया जिसमे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक,मोबाइल एसेसिरीज आदि की दुकान खोलकर चलाई जा रही थी। जप्त वाहनों को परिवहन कार्यालय रीवा लाया गया और वाहन सुरक्षित खड़ा कराया गया। विभाग द्वारा सभी वाहन मालिकों को मूल दस्तावेज सहित निर्धारित समय के अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज सही न होने या मॉडिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले और अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे वाहनों के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे वाहन के मूल पंजीयन का भी पता नहीं चलता। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में किसी भी तरह का अवैध संशोधन न करवाएं।

मानस भवन के नवनिर्माण की तैयारी तेज, जिला प्रशासन ने 3 करोड़ का प्रस्ताव भेजा

रीवा। नगर के हृदय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक–आध्यात्मिक केंद्र मानस भवन के कायाकल्प को लेकर लंबे समय से चली आ रही पहल अब गति पकड़ चुकी है। मानस मंडल के अध्यक्ष सुभाष बाबू पाण्डेय द्वारा उठाई गई मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निर्देशन में भवन के नवनिर्माण का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय जिला प्रशासन को निर्माण का विस्तृत अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।

बच्चों को साइबर सुरक्षा, गुड टच बैड टच और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव की दी गई जानकारी

मिशन वात्सल्य योजना के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गत दिवस ज्ञानोदय विद्यालय एवं छात्रावास में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बच्चों को करियर गाइडेंस के तहत पुलिस विभाग में जाने के लिए तैयारी करने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके साथ ही साइबर अपराध से सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक किया। थाना प्रभारी निशा मिश्रा बच्चों को हिडन कैमरे तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने गुड टच बैड टच और विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षिका मनु सिंह ने बच्चों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने की टिप्स बताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा और सोशल मीडिया से भी दूर रहना होगा।

कार्यशाला में बेनिसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला, अमर सिंह ने बच्चों से कहा कि अपना रोल मॉडल किसी सफल व्यक्ति को बनाएं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास में हुआ जागरूकता कार्यक्रम – मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाबू जगजीवन राम छात्रावास में भी बालिकाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण अधिकारी स्वाती श्रीवास्तव, बाल संप्रेषण गृह की अधीक्षक अर्चना पचौरी तथा अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के समन्वयक सुमित सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, बाल अधिकारों एवं सुरक्षा के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन वात्सल्य का उद्देश्य प्रत्येक बालक एवं बालिका को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर हॉस्टल अधीक्षका सहित छात्रावास की सभी बालिकाएं उपस्थित रहीं।

जिस भी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में आपका नाम है, वहाँ के बीएलओ से तुरंत संपर्क करें

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की मतदाताओं से अपील

मीडिया ऑडिटर, रीवा (निप्र)। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान करके बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइजेशन का काम तेजी से जारी है। इसमें न केवल ईआरओ और एईआरओ की टीमें बल्कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, महिला बाल विकास विभाग तथा राजस्व विभाग की टीमें भी कार्य कर रही हैं।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है। कलेक्टर ने वीडियो संदेश में कहा है कि मतदाता सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में रहे। जिस भी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में आपका नाम है, वहाँ के बीएलओ से तुरंत संपर्क करें। आपके घर में जो गणना पत्रक दिए गए हैं, उन्हें भरकर अपने बीएलओ को अवश्य जमा करा दें। जो गणना पत्रक भरे हुए प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा और उन्हीं लोगों के नाम आगे मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। यदि किसी मतदाता को गणना पत्रक भरने में या यह समझने में दिक्कत आ रही है कि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में कहाँ पर था तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ को 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है। मतदाता बीएलओ की मदद से अपना सीरियल नंबर (क्रम संख्या) और पार्ट नंबर (भाग संख्या) बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने घर के सभी मतदाताओं के फॉर्म भरकर जल्द से जल्द अपने बीएलओ को जमा कराएँ।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।